Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

विशेषांक-2

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-07-08 01-15—16-30 अप्रैल, 2024 (संयुक्तांक) ₹20

'संकल्प पत्र 140 करोड़ नागरिकों के सपनों को साकार करेगा'

नई दिल्ली में 14 अप्रैल, 2024 को 'भाजपा संकल्प पत्र' जारी होने से पूर्व भाजपा मुख्यालय (विस्तार) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह और श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 14 अप्रैल, 2024 को भाजपा मुख्यालय (विस्तार) में 'भाजपा संकल्प पत्र' जारी होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह और श्रीमती निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली में 14 अप्रैल, 2024 को भाजपा मुख्यालय (विस्तार) में 'भाजपा संकल्प पत्र' जारी होने से पूर्व बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 14 अप्रैल, 2024 को भाजपा मुख्यालय (विस्तार) में बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 14 अप्रैल, 2024 को लोकसभा चुनाव– 2024 के लिए 'भाजपा संकल्प पत्र' जारी करने के दौरान प्रत्येक GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति) लाभार्थियों को संकल्प पत्र की एक प्रति सौंपते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

भाजपा का संकल्प 'मोदी की गारंटी 2024' का लोकार्पण 06

विकसित भारत के संकल्प के लिए जनता भाजपा की ताकत बढ़ाए : नरेन्द्र मोदी

1. यह संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है : जगत प्रकाश नड्डा 12
2. मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी : राजनाथ सिंह 14
3. संकल्प पत्र 2024 16
4. विकसित भारत@2047 20
5. गरीब कल्याण: मोदी की गारंटी 24
6. अमृत पीढ़ी की नई उड़ान 26
7. अन्नदाताओं की समृद्धि: मोदी की गारंटी 31
8. वीमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़ते कदम 35
9. मजबूत अर्थव्यवस्था से विकसित भारत 40
10. राष्ट्रीय सुरक्षा: मोदी की गारंटी 44
11. सांस्कृतिक कायाकल्प: मोदी की गारंटी 46
12. सुशासन राष्ट्र के विकास की कुंजी है 48
13. पर्यावरण संरक्षण: हमारा दायित्व 52
14. विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी: अनुसंधान को प्रोत्साहन 53
15. पूर्वोत्तर: भारत का विकास इंजन 54
16. विश्वमित्र बन उभरा भारत 55
17. मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर: मोदी की गारंटी 56

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

पिछले 10 वर्षों में हमने असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी पूरा कर दिखाया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है कि बड़े कामों का दमखम सिर्फ भाजपा और एनडीए में है।

(16 अप्रैल, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है। गांव के विकास और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को समर्पित है। विगत 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने संकल्प को जमीन पर चरितार्थ किया है।

(14 अप्रैल, 2024)

अमित शाह

मोदी सरकार ने बीते एक दशक में देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान, वीरों को सम्मान, गरीब कल्याण व वैश्विक सम्मान का नया कीर्तिमान बनाया है। आज गढ़वाल जनसभा में उपस्थित विशाल जनसमूह इस बात का प्रमाण है कि आएंगे तो मोदीजी ही।

(16 अप्रैल, 2024)

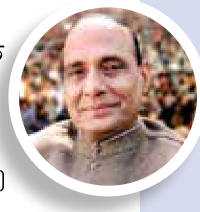

राजनाथ सिंह

सारे अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि मोदीजी के नेतृत्व में अगर भारत ऐसे ही विकास करता रहा तो 2027 आते-आते हमारा यह भारत दुनिया की Top 3 Economies में आकर खड़ा हो जायेगा।

(19 अप्रैल, 2024)

बी.एल. संतोष

श्रीमती इंदिरा गांधी और डीएमके के थिरु करुणानिधि ने मिलकर श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप उपहार में देने का खेल खेला, हालांकि भारत के क्षेत्र में पानी की कमी थी। यह तमिलनाडु के मछुआरों की आए दिन होने वाली समस्याओं और गिरफ्तारियों का मूल कारण रहा।

(01 अप्रैल, 2024)

पीयूष गोयल

धारा 370 हटाने को लेकर सवाल उठाने वाले लोग, शहीद सैनिकों और कश्मीर की सुरक्षा में तैनात देशभर के वीर सपूतों का अपमान कर रहे हैं।

(7 अप्रैल, 2024)

संपादकीय

यही समय है, सही समय है

व्यापक दृष्टि, भविष्योन्मुखी कार्य-योजनाएं एवं 'विकसित भारत' के दृढ़ संकल्प से प्रेरित भाजपा संकल्प पत्र- 'मोदी की गारंटी 2024' का पूरे देश में स्वागत हुआ है। भाजपा संकल्प पत्र जारी होते ही इसकी समग्रता, देश की अंतर्निहित शक्तियां एवं अपार संभावनाओं की गहरी समझ, देश के लोगों की असीमित क्षमता पर विश्वास एवं एक दशक पूर्व जो असंभव प्रतीत होता था, उसको संभव कर दिखाने की दृष्टि के कारण देशभर में इसकी प्रशंसा हो रही है। 'मोदी की गारंटी 2024' ने जन-जन की आकांक्षाओं एवं स्वप्नों को अनेक अभिनव कार्यक्रमों, परिवर्तनकारी योजनाओं एवं प्रेरक लक्ष्यों के माध्यम से भाजपा के संकल्प में संजोया गया है। संकल्प पत्र के केंद्र में जहां लोगों की वर्तमान आवश्यकताएं हैं, वहीं इसकी दृष्टि नए क्षितिजों को छूती है और उसके पार भी जाती है। संकल्प पत्र केवल बड़ा नहीं सोचता, बल्कि उन बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव भी कर रहा है। यह आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के कार्यक्रम एवं योजनाएं हैं जो अपने लिए बड़े लक्ष्यों को निर्धारित कर उनके लिए अथक परिश्रम करने के लिए कृतसंकल्पित है। 'मोदी की गारंटी' के रूप में प्रस्तुत भाजपा संकल्प पत्र देश को परिवर्तनकारी यात्रा के दूसरे चरण में ले जाने के लिए तत्पर है, जिससे 'विकसित भारत' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

भाजपा संकल्प पत्र 'मोदी की गारंटी 2024' के रूप में जारी हुआ है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर ठीक ही कहा है कि 'मोदी की गारंटी का अर्थ है गारंटी पूरा होने की गारंटी।' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अपनी अद्भुत उपलब्धियों से पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालना, युवाओं के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोलना, अन्नदाताओं का सशक्तीकरण, वीमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में देश को बढ़ाना, धारा 370 का निरस्तीकरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं तीन तलाक पर कड़े कानून, सीएए का कार्यान्वयन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना और इसी प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्य आज 'विकसित भारत' के स्वप्न का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भाजपा संकल्प पत्र ने अनेक चुनौतियों के आधुनिक तकनीक एवं नई प्रौद्योगिकियों के जरिए दूरदर्शितापूर्ण एवं अनुपम समाधान प्रस्तुत किए हैं। जीरो-इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राप्त करने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से बिजली बिल तो शून्य होगा ही, साथ ही लाभार्थी की आय में भी वृद्धि होगी। गैस सिलेंडर की जगह अब पाइपलाइन से हर बड़े शहर एवं कस्बे को जोड़ने से आमजन को सस्ती गैस उपलब्ध होगी। देशभर में चार्जिंग स्टेशन का तंत्र विकसित होने से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा परंतु इससे युवाओं के लिए अनेक 'ग्रीन-जॉब्स' उपलब्ध होंगे। अब तक अत्यंत सफल रही मुद्रा एवं स्वनिधि योजना के विस्तार से महिला एवं निम्न आय वर्ग की उद्यमशीलता को नए पंख लगेंगे और उनके लिए समृद्धि के द्वार खुलेंगे। संकल्प-पत्र में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर के लिए भी 'आयुष्मान भारत' के लाभ का मोदी की गारंटी है। भारत को न्यूट्रीशन एवं खाद्य-प्रसंस्करण हब बनाने, किसान समृद्धि केंद्र खोलने, नैनो यूरिया को बढ़ावा देने जैसी अनेक भविष्योन्मुखी योजनाओं की मोदी की गारंटी से न केवल पूरे कृषि जगत में व्यापक परिवर्तन आएगा, बल्कि देश के 'अन्नदाता' वैश्विक स्पर्धा में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगे।

> **'मोदी की गारंटी' के रूप में प्रस्तुत भाजपा संकल्प पत्र देश को परिवर्तनकारी यात्रा के दूसरे चरण में ले जाने के लिए तत्पर है, जिससे 'विकसित भारत' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा**

भारत, वर्तमान में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अमृतकाल में देश के भविष्य को पूरी तरह से बदलने का सुनहरा अवसर आज सबके सामने है। सामूहिक प्रयास एवं अटूट प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित भारत' के स्वप्नों को साकार करने का संकल्प लिया है। इन प्रयासों में हर परिवार, हर गांव, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, आज कोई भी अछूता नहीं है। सोशल, फिजिकल एवं डिजिटल अवसंरचना की दृष्टि के साथ नए सैटेलाइट नगर, सुदृढ़ विमानन क्षेत्र, देश के चारों भाग में बुलेट ट्रेन के साथ-साथ सुरक्षा, खाद्य तेल एवं ऊर्जा आयात में आत्मनिर्भरता की मोदी की गारंटी से देश में युवाओं के लिए नए संभावनाओं एवं ग्रीन-जॉब्स जैसे अनेक अवसरों के द्वारा खुलेंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई देशों के मध्य युद्ध, उथल-पुथल एवं तनाव के संदर्भ में ठीक ही कहा है कि आज भारत को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है जो विदेश की धरती पर भी अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा देश का भविष्य सुरक्षित रखने की गारंटी हो। पिछले दस वर्षों की चमत्कारिक उपलब्धियों के आलोक में यदि देखा जाए, तब इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में—

'यही समय है, सही समय है,
भारत का अनमोल समय है।' ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

‘भाजपा का संकल्प—मोदी की गारंटी 2024’ का लोकार्पण

विकसित भारत के संकल्प के लिए जनता भाजपा की ताकत बढ़ाए : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2024 को भाजपा केंद्रीय कार्यालय विस्तार में 2024 लोकसभा चुनाव हेतु भाजपा के संकल्प पत्र ‘भाजपा का संकल्प—मोदी की गारंटी 2024’ का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंच पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री एवं भाजपा संकल्प-पत्र समिति के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के साथ-साथ केंद्रीय वित्त मंत्री एवं भाजपा संकल्प-पत्र समिति की संयोजक श्रीमती निर्मला सीतारमण भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। श्री मोदी ने अलग-अलग वर्ग और क्षेत्र के लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली प्रति सौंपी। ये ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की किसी न किसी योजना से लाभ मिला है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार के पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया

भाजपा का संकल्प—मोदी की गारंटी 2024' लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में वैशाख का, असम में बिहू, ओडिशा में पाना संक्रांति, केरल में बिशु, तमिलनाडु में नववर्ष पुथांडु—सब जगह हर्ष का वातावरण है। नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। मां कात्यायनी अपनी दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सोने में सुहागा कि आज बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती भी है।

लाखों नागरिकों का धन्यवाद

श्री मोदी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने मूल्यवान सुझाव देने और संकल्प पत्र बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने पर देशभर के लाखों नागरिकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। संकल्प-पत्र समिति के अध्यक्ष श्री राजनाथ जी और उनकी टीम के साथ आठ लाख सुझाव भेजने वाले देश के नागरिकों का भी अभिनंदन करता हूं।

संकल्प-पत्र की शुचिता पुनः स्थापित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूरा देश भाजपा के संकल्प पत्र की प्रतीक्षा करता है क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में अपने संकल्प पत्र के हर बिन्दु को गारंटी के रूप में धरातल पर उतारा है और संकल्प-पत्र की शुचिता को पुनः स्थापित किया है। यह संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ (GYAN) गरीब, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त करता है। भाजपा सरकार का ध्यान डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ और निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ ऑपर्चुनिटी (Quantity of Opportunity) और क्वालिटी ऑफ ऑपर्चुनिटी (Quality of Opportunity) दोनों पर जोर दिया गया है।

> **भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का संकल्प लिया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गरीब के भोजन की थाली पोषणयुक्त और सस्ती होने के साथ मन को संतोष देने वाली हो, जिससे गरीब का पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरी रहे**

युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब

श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार ने इन्फास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने की बात की है और अब दूसरी तरफ भाजपा स्टार्टअप और वैश्विक केन्द्रों को बढावा देकर हाईवैल्यूज सर्विसिंग पर भी जोर देने जा रही है। भाजपा के इस संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का भी प्रतिबिंब है। भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर यह सिद्ध किया कि भाजपा सरकार परिणाम लेकर आती है लेकिन काम यहां पर ही नहीं रुकता क्योंकि जो लोग गरीबी से बाहर आए हैं उनको लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता होती है क्योंकि गरीबी से बाहर निकलते व्यक्ति को एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से गरीबी में धकेल सकती है। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का संकल्प लिया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गरीब के भोजन की थाली पोषणयुक्त और सस्ती होने के साथ मन को संतोष देने वाली हो, जिससे गरीब का पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरी रहे। मोदी की गारंटी है कि सभी जनऔषधि केंद्रों पर 80 प्रतिशत छूट के साथ सस्ती दवाइयां मिलती रहेंगी और जनऔषधि केंद्रों का विस्तार भी किया जाएगा। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने 70 वर्ष की आयु के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे ने लाने का बड़ा निर्णय लिया है। 70 साल का हर एक बुजुर्ग चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग का सभी को हमारी सरकार 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा देगी।

गरीबों को पक्के घर

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार

ने अब तक गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं और इस योजना का विस्तार करते हुए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ पक्के घर और बनाने का संकल्प लिया है। अभी तक भाजपा सरकार ने सस्ते सिलेंडर घर-घर पहुंचाए हैं लेकिन अब भाजपा घर-घर पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का काम भी तेजी से पूरा करेगी। भाजपा सरकार ने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए हैं और अब भाजपा सरकार करोड़ों परिवारों का बिजली बिल शून्य करने और बिजली से कमाई का अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रही है। इसी को लेकर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है और 1 करोड़ लोग इस योजना के तहत पंजीकरण कर चुकी है। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर अधिक तेजी से काम किया जाएगा, क्योंकि इससे घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी होगी साथ-साथ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने पर जनता का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बचेगा।

जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिले लाभ के कारण बीते वर्षों में करोड़ों लोग उद्यमी बने हैं। इस योजना से करोड़ों रोजगार सृजित हुए हैं और लाखों लोग रोजगार सृजक बने हैं। योजना की इस सफलता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि अब मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। भाजपा के इस निर्णय से उद्योग 4.0 की जरूरतें पूरी होंगी और युवाओं को नई ताकत मिलेगी। इस योजना से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए अधिक धनराशि और अधिक संसाधन मुहैया होंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने आजादी के बाद पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों की गरिमा को

सुरक्षित रखते हुए उन्हें ब्याज के चक्कर से मुक्ति दिलाई है। आज इन लोगों को बैंक में बिना कोई गारंटी दिए ऋण मिल जाता है क्योंकि मोदी ने इनकी गारंटी ली है। इस

> **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिले लाभ के कारण बीते वर्षों में करोड़ों लोग उद्यमी बने हैं। इस योजना से करोड़ों रोजगार सृजित हुए हैं और लाखों लोग रोजगार सृजक बने हैं। योजना की इस सफलता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि अब मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा**

योजना की ऋणसीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाया जाएगा और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाया जाएगा। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है।

नारी केन्द्रित विकास

श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें विशेष आवास सुनिश्चित किए जाएंगे। भाजपा ने ट्रांसजेंडरों को पहचान-प्रतिष्ठा दी है और अब उन्हें आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नारी केन्द्रित विकास करते हुए भारत आज पूरे विश्व को दिशा दिखा रहा है। पिछले दस वर्ष नारी गरिमा और नारी को नए अवसर देने को समर्पित रहे हैं और आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते दस वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, भाजपा इन सहायता समूहों को अब आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खुदरा और पर्यटन जैसी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करेगी। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और भाजपा अब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएगी, ये मोदी की गारंटी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव गांव में महिलाएं ड्रोन पायलट बनेंगी। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं का सम्मान और कमाई बढ़ी है और ये महिलाएं खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई हैं। इसी प्रकार महिला खिलाड़ियों को खेलों मे आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। भाजपा महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने को अपने संकल्प का पालन करते हुए अब सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के

लिए अभियान चलाएगी।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाएंगे

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखती है इसीलिए खेती, पशुपालन और मछलीपालन सहित सभी क्षेत्र के लोगों को सशक्त किया जा रहा है। भाजपा ने पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में जोड़ा है। देश को 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना जारी रहेगा। भाजपा सरकार सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी जिसके अंतर्गत देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। भाजपा सरकार ने हाल ही विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए भाजपा सरकार सुपर फूड पर अधिक बल देने वाली है। श्री अन्न पैदा करने वाले दो करोड़ से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर प्रकार की मदद की जाएगी। भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के नए क्लस्टर्स का गठन करेगी, मछलीपालन क्षेत्र के लिए भी नए उत्पादन क्लस्टर बनाएगी और मछुआरों को सीविड एवं मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती और नैनो यूरिया के अधिकतम प्रयोग पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केन्द्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है और ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट ग्रामीण क्षेत्र के लिए नए ग्रोथ इंजन बनेंगे।

> **भाजपा ने पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में जोड़ा है। देश को 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना जारी रहेगा। भाजपा सरकार सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी जिसके अंतर्गत देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी**

जनजातीय गौरव अभियान को गति देंगे

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनजातीय समाज के गौरव को मान्यता देते हुए देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा और जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्रभर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी, डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की स्थापना करेगी, वन उपज आधारित स्टार्ट अप एवं स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा देगी और 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष्य को भी पूरा करेगी। भाजपा विकास भी और विरासत भी के मंत्र में विश्वास करती है। भाजपा पूरे विश्व में थिरूवल्लुवर सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करेगी। विश्व की सबसे पुरानी भाषा और देश का गौरव तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी। भाजपा पूरे विश्व के पर्यटकों को देश की विरासत से जोड़ेगी और नालंदा सहित देश की विरासतों को वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेगी। टूरिज्म डेस्टिनेशन रैंकिंग के आधार पर पर्यटक स्थलों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। भाजपा ईकोटूरिज्म के नए केन्द्र स्थापित करेगी।

नए सैटेलाइट टाउन बनाएंगे

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा तीन तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर से 21वीं सदी के भारत की बुनियाद मजबूत करने जा रही है, जिसमें सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। भाजपा सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नए-नए शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है और दुर्घटनाएं कम करने हेतु ट्रक ड्राइवरों के लिए हाइवे के पास एक बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए देश में हाइवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवेज को आधुनिक बनाया जा रहा है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 5-जी का विस्तार किया जा रहा है, 6-जी पर काम किया जा रहा है और उद्योग 4.0 को केन्द्र रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। सरकार की ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को

ऑनलाइन बनाया जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है तथा ओएनडीसी और टेलीमेडिसिन का विस्तार किया जा रहा है। इन तीनों इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की गति और स्केल इतना तेजी से बढ़ेगा कि इससे स्कोप भी बढ़ जाएगा। ये भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश की पूर्व सरकारें शहरीकरण को चुनौती मानती थीं लेकिन भाजपा उसे अवसर के रूप में देखती है। भाजपा सरकार देश में नए नए सैटेलाइट टाउन बनाएगी जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे। देश के एविएशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा खास ध्यान दे रही है। देश ने हाल ही 1000 से अधिक विमानों की डील की है, ये विमान अपने साथ रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएंगे। ये सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं। भाजपा देश के कोने-कोने में वंदे भारत ट्रेन का विस्तार करेगी और देश में वंदे भारत के तीन मॉडल संचालित होंगे—वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन का काम पूरा होने वाला है। भाजपा का संकल्प है कि आने वाले समय में भारत की चारों दिशाओं में एक-एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। रक्षा, खाद्य तेल और ऊर्जा आयात सहित हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता बढ़ाना भाजपा का संकल्प है। ये परियोजनाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही देश के पर्यावरण की भी सुरक्षा करेंगी। इससे देश में बड़ी संख्या में हरित रोजगार पैदा होंगी।

> **देश की पूर्व सरकारें शहरीकरण को चुनौती मानती थीं लेकिन भाजपा उसे अवसर के रूप में देखती है। भाजपा सरकार देश में नए नए सैटेलाइट टाउन बनाएगी जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे। देश के एविएशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा खास ध्यान दे रही है। देश ने हाल ही 1000 से अधिक विमानों की डील की है, ये विमान अपने साथ रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएंगे**

नि:शुल्क यात्रा की ओर

श्री मोदी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 वर्ष पहले एक साल में मात्र 2000 EV की बिक्री हुई थी, लेकिन आज जबकि पिछले ही वर्ष देश में 17 लाख से अधिक EV बिके हैं। पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। भाजपा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पीएम सूर्य के माध्यम से घरों में निःशुल्क चार्जिंग की शुरुआत कर निःशुल्क यात्रा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इलेक्ट्रिक के उभरते हुए क्षेत्र के कारण देश भर में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया भर के उभरते क्षेत्रों का ग्लोबल हब बनाने का है। वह समय ज्यादा दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, लीगल इन्श्योरेन्स और कान्ट्रैक्टिंग एण्ड कमर्शियल जैसे क्षेत्रों का ग्लोबल हब बन जाएगा। वह दिन भी दूर नहीं जब दुनिया भर के बड़े–बड़े इकोनॉमिक केंद्र भारत में होंगे और देश ग्लोबल कैपबिलिटी सेंटर, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर और ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर का बहुत बड़ा हब बनेगा। भारत स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में भी दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और यह क्षेत्र देश को कल्पना से परे अवसर प्रदान करेगा।

भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई

श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं और युद्ध की स्थिति के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तनावपूर्ण क्षेत्रों में रहे भारतीयों की सुरक्षा भाजपा के लिए प्राथमिकता है। जब दुनिया भर में ऐसा तनावग्रस्त माहौल बना हो तो भारत में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। एक ऐसी सरकार जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर, विकास की ओर आगे ले जाए, जिसके लिए भाजपा संकल्पबद्ध है। भाजपा का यह संकल्प पत्र ऐसी ही सरकार की गारंटी देता है। भारत मानवता के कल्याण के लिए विश्वबन्धु के तौर पर निरंतर प्रयासरत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी देशहित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती, भाजपा के लिए देश दल से बड़ा है। भाजपा ने नारी शक्ति अधिनियम को कानून बनाया, धारा 370 को हटाया और सीएए को देश में लागू किया। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। भाजपा एक देश, एक चुनाव के सपने को लेकर आगे बढ़ रही है और देशहित के लिए यूसीसी को भी आवश्यक मानती है। भ्रष्टाचार गरीब और मध्यम परिवार के अधिकार को छीनता है भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हो गए हैं। गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर निरंतर सख्त कार्रवाई मोदी की गारंटी है।

> भारतीय जनता पार्टी देशहित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती, भाजपा के लिए देश दल से बड़ा है। भाजपा ने नारी शक्ति अधिनियम को कानून बनाया, धारा 370 को हटाया और सीएए को देश में लागू किया। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे

नये भारत को रोकना असंभव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1 हजार वर्षों के लिए, भारत के भविष्य को तय करने वाला यह उत्तम समय और अवसर है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के बाद तेजी के कार्य शुरू हो जाएगा। भाजपा सरकार ने पहले से ही प्रारम्भिक 100 दिनों के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। देश के 140 करोड़ देशवासियों का ऐम्बिशन 'मोदी का मिशन है'। देश ने चंद्रयान की सफलता देखी है और अब गगनयान का गौरव भी अनुभव करेगा। अभी देश ने जी-20 में भारत का स्वागत देखा और अब ओलम्पिक की मेजबानी में भी पूरी ताकत लगा देंगे। नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है और अब इसको रोकना असंभव है। मैं इस संकल्प पत्र को मोदी के गारंटी के रूप में 140 करोड़ देशवासियों के समक्ष रख रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए भाजपा यह संकल्प पत्र लेकर आई है। मां भारती के कोटि-कोटि जनों के कल्याण के लिए और विकसित भारत के संकल्प के लिए देश की जनता भाजपा की ताकत बढ़ाए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ■

यह संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है : जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में 14 अप्रैल, 2024 को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में लोकसभा चुनाव 2024 हेतु भाजपा के संकल्प पत्र 'भाजपा का संकल्प—मोदी की गारंटी 2024' का लोकार्पण किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा-सुमन भी अर्पित किये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनसंघ काल से ही अपना वैचारिक अधिष्ठान होने के कारण हर चुनाव में अपनी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने भाजपा सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित किया

भाजपा का संकल्प—मोदी की गारंटी 2024’ लोकार्पण के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा देश की सेवा का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान प्रशासक होने के नाते अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और पार्टी को प्राथमिकता देते हुए सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए सदैव ही अपना महत्वपूर्ण समय पार्टी को देते हैं। श्री नड्डा ने सभी व्यस्तताओं के बीच और चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भाजपा संकल्प पत्र विमोचन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आभार व्यक्त किया। श्री नड्डा ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर जी ने अपना सारा सामाजिक जीवन न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बाबासाहब अंबेडकर के विचार पर चलते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया है।

अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समर्पित सरकार

भाजपा की वैचारिक यात्रा को याद करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनसंघ काल से ही अपने वैचारिक अधिष्ठान होने के कारण हर चुनाव में अपनी वैचारिक यात्रा को

आगे बढ़ाया है। 1952 में जिस विचार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी ने साझा किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, भाजपा उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भरसक प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र इसी वैचारिक अधिष्ठान का पर्याय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ ने एकात्म मानववाद के विचार को रखा और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इसी विचार को अंत्योदय के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी विचार को समाहित करते हुए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र के साथ काम किया। 2014 में संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भाजपा की सरकार गरीब, गांव के विकास और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समर्पित सरकार है। विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बखूबी गांव और गरीब की चिंता करते हुए, इन सारे आयामों को आगे बढ़ाया है।

श्री नड्डा ने कहा कि जब देश की जनता जब पूर्ण बहुमत की सरकार चुनती है, तो उस सरकार के कार्य परिणाम भी बहुत स्पष्ट होते हैं। 2014 में भाजपा का वोट प्रतिशत 31% तक पहुंचा था और लोकसभा में भाजपा ने 282 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 2019 में भाजपा ने अपने ही रिकार्ड को तोड़ते हुए, अपना वोट प्रतिशत 37% तक पहुंचाया और 303 लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज की। इस स्पष्ट बहुमत को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांव, गरीब, वंचित, दलित, महिला, युवा और किसान को समर्पित किया।

> जब देश की जनता जब पूर्ण बहुमत की सरकार चुनती है, तो उस सरकार के कार्य परिणाम भी बहुत स्पष्ट होते हैं। 2014 में भाजपा का वोट प्रतिशत 31% तक पहुंचा था और लोकसभा में भाजपा ने 282 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 2019 में भाजपा ने अपने ही रिकार्ड को तोड़ते हुए, अपना वोट प्रतिशत 37% तक पहुंचाया और 303 लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज की

सबका विकास

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3 लाख 80 हजार किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण किया गया और 60 हजार गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। पहले गांव के सशक्तीकरण का विचार भी कल्पना के समान था, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फ़ाइबर से जोड़ा गया है और दूरगामी क्षेत्रों तक इंटरनेट सेवा पहुंच रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क प्रदान की गई, जिसके कारण आज के समय में देश की 25 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा से बाहर आ गयी है। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत में अतिगरीबी 1% से भी कम रह गई है। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के शासन में इंदिरा आवास योजना के तहत एक ब्लॉक में 2 घर आवंटित किए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किए गए है। महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से 50 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत माताओं और बहनों को लगभग 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नारी शक्ति को सम्मान देते हुए लगभग 11 करोड़ इज्जतघर का निर्माण करवाया है।

मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी

लोकतंत्र में बहुमत की सरकार के लाभ बताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि जनता ने देश में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनायी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। कई दशकों तक राम मंदिर का मुद्दा अधर में लटका हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी, 2024 को प्रभु

शेष पृष्ठ 15 पर...

'भाजपा का संकल्प—मोदी की गारंटी 2024' का लोकार्पण

मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी : राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में 14 अप्रैल, 2024 को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में लोकसभा चुनाव 2024 हेतु भाजपा के संकल्प पत्र 'भाजपा का संकल्प—मोदी की गारंटी 2024' का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री एवं भाजपा संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है, इसीलिए भाजपा का संकल्प पत्र भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक दलों के संकल्प पत्र के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। आगामी वर्षों में देश को विकसित और सशक्त बनाने के लिए भाजपा के संकल्पों को लोकसभा चुनाव 2024 के संकल्प पत्र के रूप में पेश किया।

भाजपा जो कहती है, वह करती है

श्री राजनाथ सिंह ने 'संकल्प पत्र' की अध्यक्षता का दायित्व देने के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 और 2019 के संकल्प पत्रों में देश से किए गए सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। भाजपा अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से स्वाभिमानी और सशक्त भारत के निर्माण का रोडमैप पेश करने के साथ समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता भी जताती है। 5 वर्ष पूर्व 2019 में 'संकल्पित भारत—सशक्त भारत' के उद्घोष के साथ जो घोषणा पत्र भाजपा ने पेश किया था, उसमें आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत की संकल्पना के साथ 2047 के भारत की रूपरेखा को भी देश के सामने रखा गया था, उसी भावना के अनुरूप भाजपा शासन में कार्य किए गए और वर्ष 2019 के उन सभी संकल्पों को 2024 तक पूरा किया गया है। भाजपा जो कहती है, वह करती है। आज देश के नागरिक भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं, यही विश्वसनीयता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।

> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 और 2019 के संकल्प पत्रों में देश से किए गए सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। भाजपा अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से स्वाभिमानी और सशक्त भारत के निर्माण का रोडमैप पेश करने के साथ समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता भी जताती है

गरीब कल्याण के प्रति संवेदनशीलता

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर अपना वादा पूरा किया है। महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए संसद भवन का उद्घाटन होते ही सबसे पहले नारी वंदन अधिनियम को पेश किया गया और उसे पारित कराया गया। संकल्प पत्र में शामिल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के वादे को भी पूरा किया गया है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा समावेशी विकास और गरीब कल्याण की बात करती है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरीब कल्याण के प्रति संवेदनशीलता है कि आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बीते 5 वर्षों में 'संकल्पित और सशक्त भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य किए हैं।

संकल्प पत्र की विशेषताएं

श्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के नए संकल्प पत्र को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस संकल्प पत्र को बनाने 4 लाख सुझाव नमो एप के माध्यम से, लगभग 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से और कुल 15 लाख सुझाव समिति के पास अलग-अलग माध्यमों से आए हैं। इनमें से मुख्य मुद्दों को छांटकर उन पर चर्चा की गई है।

> आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा समावेशी विकास और गरीब कल्याण की बात करती है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरीब कल्याण के प्रति संवेदनशीलता है कि आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन दिया जा रहा है

2047 तक विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भाजपा संकल्पना प्रस्तुत कर रही हैं, वह 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के आकार और विस्तार को दर्शाता है। श्री राजनाथ सिंह ने अंत में कहा कि इस संकल्प पत्र को तैयार करने में प्रतिदिन व्यस्तताओं के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लंबे समय तक संकल्प-पत्र के लिए मार्गदर्शन दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मविश्वास से विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनहित में सभी प्राप्त सुझावों को संकलित और अध्ययन करके संकल्प पत्र के रूप में तैयार करने के लिए भाजपा चुनाव संकल्प-पत्र समिति के सदस्यों की सराहना करते हैं। ▪

संकल्प पत्र को 24 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 10 सामाजिक वर्ग बनाए गए हैं जिनमें गरीब, युवा, माध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान, मछुआरे, वंचित वर्ग, अन्य पिछड़े व कमजोर वर्ग शामिल हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में प्रशासनिक मुद्दों को 14 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें—

1. **विश्वबन्धुत्व : भारत से अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है**
2. **सुरक्षित भारत : भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा**
3. **समृद्ध भारत**
4. **वैश्विक विनिर्माण केंद्र**
5. **विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा**
6. **जीवन जीने में आसानी**
7. **विरासत का विकास**
8. **सुशासन**
9. **स्वस्थ भारत**
10. **गुणवत्तापूर्वक शिक्षा**
11. **खेल का विकास**
12. **सभी क्षेत्र का विकास करना**
13. **नवाचार और प्रौद्योगिकी और**
14. **सतत विकास, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बात है।**

पृष्ठ 13 का शेष...

श्रीराम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला को टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में विराजमान किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और जनता के पूर्ण बहुमत के आशीर्वाद से तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुस्लिम बहनों को आजादी मिली। 30 वर्षों तक महिला आरक्षण को लेकर राजनीति होती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करवाकर, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। कोविड महामारी के समय भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'जान है तो जहान है' के मंत्र पर काम करते हुए लॉकडाउन लगाकर 2 महीनों के भीतर देश को महामारी से लड़ने के लिए तैयार किया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 'जान भी है, जहान भी है' के मंत्र को सिद्ध करके दिखाया। पूरा विश्व इस बात का लोहा मानता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कोरोना से लड़ने की रणनीति सबसे मजबूत और कारगर थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 महीने के अंदर देश को कोरोना की 2 वैक्सीन देकर जनता को महामारी के भय से मुक्त करवाया और दुनियाभर के 100 से अधिक देशों को भारत में बनी वैक्सीन मुहैया कारवाई गई। श्री नड्डा ने कहा कि पिछले 10 वर्ष इस बात का प्रमाण है और पूरे देश ने भी इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किए जाने वाला संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है। ▪

संकल्प पत्र 2024

सुशासन और विकास के 10 साल

80+ करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 50+ करोड़ नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े जिन्हे 34 लाख करोड़ सीधे बैंक खातों में मिले, 34+ करोड़ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिला, 4+ करोड़ परिवारों को पक्के आवास मिले, 14+ करोड़ परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल मिला, 10+ करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला, 11+ करोड़ परिवारों की महिलाएं शौचालय पाकर गरिमापूर्ण जीवन जी रही हैं, 2.8+ करोड़ परिवारों को बिजली मिली, तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म किया, महिलाओं को 26 सप्ताह तक पेड मातृत्व अवकाश मिला, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए बिल पास हुआ, MSMES को 46+ करोड़ ऋण मिले जिनकी कुल लगत 27+ लाख करोड़ रुपये थी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय सहित 750 नए उच्च शिक्षा के संस्थान खुले, 11+ करोड़ किसानों को 6,000 रुपये की सम्मान निधि मिली, 4+ करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से आर्थिक सुरक्षा मिली, 11 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी से किसानों को किफायती खाद मिली, पारंपरिक कारीगरों, रेहड़ी-पटरी वालों, मजदूरों, एससी, एसटी, ओबीसी, पीवीटीजी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर आदि को विशेष योजनाओं के द्वारा सशक्त बनाया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया, वामपंथी उग्रवाद और अन्य आंतरिक खतरों का सख्ती से निपटान किया, 1.5+ करोड़ नागरिकों को संकट की स्थिति में सुरक्षित वापस लाए, राम मंदिर का निर्माण किया, आस्था की प्राचीन विरासतों का पुनरुद्धार किया, भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना, यूपीआई को विश्व स्तर पर पहुंचाया, प्रतिदिन 28 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों और 14.5 किमी रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, 3.7 लाख किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया, मानव रहित रेलवे क्रासिंग को खत्म किया, बंदरगाहों की क्षमता और हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना किया, 20+ शहरों में मेट्रो का विस्तार किया, नॉन-फॉसिल फ्यूल के द्वारा बनाई गई बिजली क्षमता को 2.5 गुना किया, आज भारत चंद्रमा तक पहुंच गया है — ऐसे कई अनगिनत कार्य पिछले 10 सालों में हुए...

गरीब परिवारजन

- पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन प्रदान करते रहेंगे
- गरीब की थाली को सुरक्षित रखेंगे
- पीएम आवास योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा और जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करते रहेंगे
- पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीबों का बिजली का बिल जीरो होगा
- आयुष्मान भारत, आरोग्य मंदिर इत्यादि जैसी योजनाओं द्वारा निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे

मध्यम-वर्गीय परिवारजन

- मध्यम वर्गीय परिवारों के घर का सपना पूरा करेंगे
- एम्स, मेडिकल कॉलेज और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं
- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, आईआईएम, एम्स और विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों को मजबूती देंगे और क्लासरूम को प्रैक्टिकल लर्निंग से जोड़ने के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू करेंगे

नारी शक्ति

- तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे
- महिला SHG को एक जिला-एक उत्पाद, एफपीओ, एकता मॉल, एक स्टेशन-एक उत्पाद जैसी योजनाएं एवं ओएनडीसी, GeM पोर्टल से जोड़कर उनके उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे
- महिलाओं की खेल और वर्कफोर्स (कार्यबल) में भागीदारी को बढ़ावा देंगे
- महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए एनीमिया, स्तन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे

युवा

- सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए कानून को सख्ती से लागू करेंगे
- आगे भी सरकारी भर्तियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे
- स्टार्टअप इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और सर्विस क्षेत्र का विस्तार करके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगे
- मुद्रा योजना में ऋण की सीमा को दोगुना कर के युवाओं में एंट्रेप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे
- खेलो इंडिया योजना का विस्तार करेंगे और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए आईओए (IOA) को समर्थन देंगे
- मेरा युवा भारत (MY Bharat) के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में युवाओं को शामिल करेंगे

वरिष्ठ नागरिक

- सत्तर वर्ष से अधिक सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में शामिल किया जाएगा
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को उनके घर तक पहुंचाएंगे और सुगम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे

किसान का सम्मान

- पीएम किसान और पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से लगातार वित्तीय सहायता

- उचित मूल्य समर्थन के साथ फसल विविधीकरण (क्रॉप डायवर्सिफिकेशन) को प्रोत्साहित करेंगे
- किसानों को समर्थन देकर दाल, खाद्य तेल और सब्जियों में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे
- श्री अन्न को एक सुपरफूड के रूप में और भारत को विश्व के मिलेट हब के रूप में स्थापित करेंगे
- प्राकृतिक खेती और नैनो यूरिया के उपयोग का प्रोत्साहन करेंगे
- डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार और फुट एवं माउथ डिजीज (एफएमडी) की रोकथाम करेंगे
- सहकार से समृद्धि के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लागू करेंगे

मत्स्य पालक परिवारजन

- पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार करके बीमा कवरेज को बढ़ाएंगे और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे
- मत्स्य पलकों की आय बढ़ने के लिए प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करेंगे और मोती एवं सी-वीड की खेती को प्रोत्साहन देंगे

श्रमिकों का सम्मान

- प्रवासी मजदूर, गिग वर्कर्स, ऑटो, टैक्सी, ट्रक ड्राइवरों का ई-श्रम पर पंजीकरण सुनिश्चित करके उनको पात्रता अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायता करेंगे
- पीएम स्वनिधि का विस्तार कर गांवों और कस्बों के रेहड़ी पटरी वालों को इस योजना में शामिल करेंगे

एमएसएमई, छोटे व्यापारी और विश्वकर्मा

- छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के विकास के लिए डिजिटल क्रेडिट विकसित करेंगे और ओएनडीसी का उपयोग करेंगे
- छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए कानूनों और जीएसटी को सरल बनाएंगे
- पीएम विश्वकर्मा योजना का विस्तार करेंगे और इसके माध्यम से विश्वकर्मा समुदाय को अधिक सशक्त बनाएंगे
- परंपरागत हस्तशिल्प, खिलौनों और खादी को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करेंगे

सबका साथ, सबका विकास

- जनजातीय संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करेंगे, 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे और डिजिटल जनजातीय कला अकादमी स्थापित करेंगे
- वन उपज पर आधारित स्टार्टअप और SHGS को प्रोत्साहन देंगे
- मुद्रा ऋण को दोगुना, पीएम स्वनिधि एवं पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं का विस्तार करके ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को आजीविका के अवसर देंगे
- पीएम आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देकर उनके अनुरूप किफायती एवं सुलभ आवास प्रदान करेंगे
- ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करेंगे

ईज ऑफ लिविंग

- प्रमुख शहरों और कस्बों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन की सुविधा देंगे
- नए सैटेलाइट टाउन्स को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करेंगे जिससे रोजगार के होंगे नए अवसर पैदा

- महानगरों में मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली विकसित करेंगे

स्वास्थ्य और शिक्षा

- एम्स से लेकर जिला अस्पतालों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक सभी स्तरों के स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करेंगे
- 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को जारी रखते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों का उन्नयन करेंगे

समृद्ध भारत और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर

- भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल निर्माण इत्यादि जैसे उभरते उद्योगों पर ध्यान देकर भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे
- वित्तीय सहायता और सरकारी खरीद के माध्यम से स्टार्टअप्स का विस्तार टियर-1 और टियर-2 शहरों में करेंगे
- वंदे भारत, वंदे स्लीपर, अमृत भारत, नमो भारत और बुलेट ट्रैन जैसी आधुनिक ट्रेनों के माध्यम से यात्री क्षमता बढ़ाएंगे और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करेंगे
- पीएम ग्राम सड़क योजना का विस्तार दूरदराज के गावों तक करेंगे
- 15,000 किमी एक्सप्रेसवे बनाएंगे
- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य माध्यम से 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे

विश्व बंधु और सुरक्षित भारत

- भरोसेमंद वैश्विक भागीदार, ग्लोबल साउथ की आवाज और फर्स्ट सिपीन्डर के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करेंगे
- भारत की ग्लोबल सोफ्ट पावर को बढ़ाएंगे और विश्व स्तर पर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेंगे

- आतंकवादी समूहों, वामपंथी उग्रवादी संगठनों एवं अन्य बाहरी और आंतरिक सुरक्षा खतरों के खिलाफ कार्यवाही के लिए सभी तरीकों का उपयोग करके भारत को सुरक्षित रखेंगे
- सैन्य थिएटर कमांड की स्थापना करेंगे और सीमाओं पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे
- घरेलू रक्षा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे

विरासत भी, विकास भी

- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास करेंगे
- अयोध्या नगरी का सर्वांगीण विकास करेंगे और दुनिया भर में रामायण उत्सव मनाएंगे
- पर्यटन के लिए सीमावर्ती गावों, नदियों, एडवेंचर, वेडिंग और ईको-टूरिज्म जैसे थीमेटिक सर्किट का विकास करेंगे

सुशासन

- भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस
- संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करेंगे
- भारतीय न्याय संहिता का कुशल कार्यान्वयन करेंगे
- वन नेशन, वन इलेक्शन का सपना साकार करेंगे

संतुलित क्षेत्रीय विकास

- नॉर्थ-ईस्ट का विकास करेंगे और शांति बनाए रखेंगे
- पूर्वी भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समर्पित पूर्वोदय मास्टर प्लान तैयार करेंगे
- द्वीपों को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों में परिवर्तित करेंगे
- हिमालय के वातावरण और संवेदनशील प्रकृति की रक्षा एवं तटीय क्षेत्रों के जलवायु का संरक्षण करेंगे

तकनीक और नवाचार

- भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान- मिशन गगनयान- लॉन्च करेंगे और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे
- मजबूत अनुसंधान के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सुचारू रूप से कार्यान्वित करेंगे
- भारत को एआई, ग्राफीन और क्वांटम तकनीकों में विश्वगुरु बनाएंगे

पर्यावरण अनुकूल भारत

- नमामि गंगे की तर्ज पर सभी प्रमुख नदियों की स्वच्छता का चरणबद्ध तरीके से सुधार करेंगे
- 131 शहरों की एयर क्वालिटी में सुधार करेंगे ▪

विकसित भारत@2047 'अमृत काल' में भारत की दिशा

"यह भारत के इतिहास का वह दौर है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है।"

"भारत के लिए यही समय है, सही समय है"

—प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को 2047 तक 'विकसित देश' बनाने हेतु 11 दिसंबर, 2023 को विकसित भारत@2047 पहल शुरू की। इस पहल में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय संतुलन और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। 'विकसित भारत' का दृष्टिकोण इस तथ्य को स्वीकार करता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक और मानव विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जो अगले 25 वर्षों में भारत के भविष्य को तय करने में सहायक सिद्ध होगा। यह अपने बीते हुए अतीत से भविष्य के भारत का पूर्वाभास देता है, जब भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था और शिक्षा, चिकित्सा, खगोल विज्ञान एवं अन्य सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा था। साथ ही, हमारी सभ्यतागत उपलब्धियां उतनी ही प्रभावशाली थीं। प्राचीन काल से ही भारत समृद्धि, ज्ञान और वैश्विक समाज को सतत प्रेरित करने वाली भूमि रहा है। हालांकि, सदियों के निरंतर आक्रमण तथा औपनिवेशिक शासन ने भारत को पस्त, आहत व घायल कर दिया। दरअसल, 'विकसित भारत' का संकल्प भारत को ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र, आर्थिक महाशक्ति और विश्वमित्र की पूर्व की स्थिति में वापस ले जाने का दृष्टिकोण है

भारत के लिए यह 'अमृत काल' क्यों?

अमृत काल का तात्पर्य भारत की आजादी की स्वर्ण शताब्दी यानी 2047 तक (आजादी का 100वां वर्ष) आने वाला 25 वर्षों का काल है। ये 25 वर्ष 2047 तक भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने तथा बेहतर जीवन स्थितियों, तीव्र विकास के साथ-साथ बुनियादी ढांचागत और तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करने का एक सुनहरा अवसर है।

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है जो अपनी 'युवा शक्ति' का लाभ उठाने के लिए तैयार है। इसलिए, यह भारत के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभ उठाने और विकसित भारत के सपने को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को इस दिशा में लगाने का सही अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात को सही ढंग से परिभाषित किया है कि आज के युवा 'परिवर्तन के वाहक' हैं और 'परिवर्तन के लाभार्थी' भी बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने भारत के भीतर और भारत के बाहर कनेक्टिविटी पर काफी ध्यान केंद्रित किया है। आज, जब संपूर्ण विश्व, वैश्विक महामारी कोरोना के बाद की स्थितियों से जूझ रहा है, भारत 7.6 प्रतिशत से भी अधिक की आर्थिक वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा, भारत आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, भारत के लिए 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए सामूहिक कदम उठाने का यह सही समय है।

अमृत काल में 'पंच प्रण'

हालांकि, भारत ने बहुत पहले ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन लोग बड़े पैमाने पर पराजयवादी मानसिकता के साथ औपनिवेशिक हैंगओवर में जी रहे थे। नवप्रवर्तन और उत्थान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सामूहिक प्रयासों का अभाव था। कांग्रेस और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के तहत पूर्ववर्ती व्यवस्था ने एक आत्मसंदेह करने वाली व्यवस्था का निर्माण किया था, जहां राष्ट्रीय

गौरव और सभ्यतागत उपलब्धियों का गौरव-गान नहीं, बल्कि उनसे घृणा की जाती थी। इससे नकारात्मकता पैदा हुई और विकास अवरुद्ध हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2022 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आने वाले 25 वर्षों के 'अमृत काल' में राष्ट्र से 'पंच प्रण' के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया है, जो इस प्रकार हैं:

- 'विकसित भारत' का संकल्प
- औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े किसी भी निशान से मुक्ति
- अपनी विरासत पर गर्व
- हमारी एकता की ताकत
- नागरिकों के कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना

पांच 'प्रणों' के जरिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए औपनिवेशिक मानसिकता के हर निशान को हटाने का आह्वान किया। मोदी सरकार के कार्यों में गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के सतत प्रयास देखे जा सकते हैं। राजपथ का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' कर दिया गया है और नेताजी की प्रतिमा उस स्थान पर स्थापित की गयी जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। 'न्यू इंडिया' का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले ही कई पहलें की जा चुकी हैं। रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर 'लोक कल्याण मार्ग' करना, बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय देशभक्ति गीतों की गूंज, भारतीय नौसेना द्वारा गुलामी की निशानी को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को अपनाना, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण, भारतीय बजट की प्रस्तुति के समय और तिथि में बदलाव, जो कई दशकों से ब्रिटिश संसद के समय के अनुरूप चला आ रहा था; एनईपी के माध्यम से छात्रों को विदेशी भाषा की बाध्यता से मुक्ति और कई अप्रचलित औपनिवेशिक कानूनों का उन्मूलन, गुलामी मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए मोदी सरकार द्वारा की गई कुछ पहल हैं, जिसने भारत को कई दशकों तक बाधित किया है।

जब पहला 'पंच प्रण' औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशानों को हटाने का आह्वान करता है, तो दूसरा 'पंच प्रण' राष्ट्र की जड़ों और भारत की महान विरासत पर गर्व करने का आह्वान करता है। इसी संकल्प के तहत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण, अंडमान के द्वीपों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखना, प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाना, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय बनाना, बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को 'पंचतीर्थ' के रूप में विकास करना, इसी संकल्प के तहत है। भारत भर में सांस्कृतिक और सभ्यतागत केंद्रों के लिए अनेक ऐसे प्रयास किये गये हैं जो भारत को 'अमृत काल' की भावना के साथ आधुनिक बनाकर देश में एक मजबूत सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरणार्थ- 'राजपथ' (औपनिवेशिक 'किंग्सवे' का हिंदी अनुवाद) उस मानसिकता को दर्शाता है जो लोगों पर शासन करना चाहता था, जबकि 'कर्तव्य पथ' नाम नागरिकों को विकसित भारत के सपनों को साकार करने में उनसे अपेक्षित कर्तव्य की याद दिलाता है। 'पंच प्रण' के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की मजबूत भावना पैदा करने के महत्व पर अत्यधिक जोर दिया है।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों में व्यापक उत्साह है और भारत को वैश्विक स्तर पर एक उभरता हुआ मजबूत देश माना जा रहा है। नवीनीकृत ऊर्जा और मिशन के साथ, ऐसा महसूस होता है कि भारत ने 2014 में वास्तविक आजादी हासिल कर ली है। शासन में एक स्पष्ट नीति और दिशा है एवं भारतीयों ने अब अपनी सभ्यता की शक्ति का उत्सव मनाते हुए अपनी पहचान पर गर्व करना आरंभ कर दिया है।

हम विकसित भारत के सपने को कैसे साकार करेंगे?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना निर्धारित की है। 'विकसित भारत' मिशन का ध्यान भारत के जनसांख्यिकीय लाभ उठाने के लिए 'GYAN'— गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित होगा।

ग़रीब

आज़ादी के 68 साल बाद यानी 2015 में भी लगभग 25 प्रतिशत भारतीय बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे थे।

हालांकि, पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी की जंजीरों से बाहर निकाला गया है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अनेक गरीबी उन्मूलन उपायों के कारण संभव हुआ है। 80 करोड़ से अधिक गरीब भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.94 करोड़ घर बनाए गए हैं और 1.12 करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों में बनाये गये हैं।

केंद्र सरकार ने महसूस किया है कि स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी कुछ बुनियादी आवश्यकताएं भारत को 'विकसित देश' बनाने के लिए अपरिहार्य हैं और इसमें जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में 14 करोड़ से अधिक नल जल कनेक्शन देकर तथा आयुष्मान भारत मिशन के तहत 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा प्रदान कर देश में गरीबों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी स्वच्छता को सुनिश्चित किया गया है।

इसके अलावा, गरीबों के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, 50 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिससे 99 प्रतिशत से अधिक भारतीय परिवारों को कवर किया गया हैं और उन्हें एक बिचौलिए-मुक्त हस्तांतरण की सुविधा मिली है, इसके तहत 312 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था के साथ-साथ इन जन धन खातों ने यह सुनिश्चित किया है कि अंतिम लाभार्थी को भ्रष्टाचार का शिकार हुए बिना कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण भेजे गए 1 में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते थे।

आवास, भोजन और स्वच्छता जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के साथ ही केंद्र सरकार गरीबों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी काफी प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोज़गार अभियान शुरू किया, जिसने करोड़ों प्रवासी श्रमिकों युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, पीएम स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडरों को पूंजीगत ऋण सुनिश्चित किया, ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें।

आज गरीबों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया जा रहा है और सम्मान के साथ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसका उद्देश्य उनकी क्षमता का लाभ उठाना और भारत के विकास मॉडल को समावेशी बनाना है। इस समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने अपनी नीति 'एक्ट फॉर नार्थईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नार्थईस्ट' के साथ गरीबी में रहने वाले और राजनीतिक उपेक्षा के कारण भेदभाव का सामना करने वाले पूर्वोत्तर के लोगों के लिए एक समावेशी वातावरण विकसित किया है।

युवा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित भारत का परिकल्पित लक्ष्य युवाओं की आधारशिला पर आधारित है, जिनमें देश में क्रांति लाने और सकारात्मक विकास लाने की क्षमता है। अगले 25 वर्ष 1922 और 1947 के बीच के 25 वर्षों जैसे होने चाहिए, जिस दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर पहुंचा और परिणाम स्वरूप 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

अमृत पीढ़ी यानी भारत के युवाओं की क्षमता का लाभ उठाने की जरूरत है, जो भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तुत की गई थी और वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में भी 'सप्तऋषि लक्ष्यों' के तहत 'अमृत पीढ़ी' को प्राथमिकता के रूप में उजागर किया गया।

नौकरी चाहने वालों के लिए नौकरी प्रदाता बनने के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए 'मेरा युवा भारत' मंच लॉन्च किया गया, जो युवाओं को तकनीक कौशल प्रदान करता है। इसने युवाओं को 'फिजिटल प्लेटफॉर्म' दिया, जो शारीरिक गतिविधि करते समय डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर देता है। इसके अलावा जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों विद्यालयों में हजारों अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं।

देश का युवा सतर्क, प्रेरित है और राष्ट्र के विकास में अत्यधिक योगदान देता है और भारतीय युवा दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले कुशल संसाधनों में से एक हैं। इसलिए, युवाओं की स्फूर्तिदायक ऊर्जा और नवीन विचारों को भविष्य के राष्ट्र-निर्माण में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्नदाता (किसान)

स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी, क्योंकि कृषि मानसून और प्राकृतिक आपदाओं पर अत्यधिक निर्भर था, जिसके परिणामस्वरूप फसलें बर्बाद हो जाती थीं। आज, भारत पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में मजबूत विकास देख रहा है और आत्मनिर्भर बन गया है।

केन्द्र सरकार ने पीएम-किसान योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से फसल बीमा सुनिश्चित किया है। इसके

अलावा, ई-नाम पहल ने किसानों को देश भर के बाजारों तक सीधी पहुंच प्रदान की है, जिससे उन्हें अधिक लाभकारी मूल्य मिल सके।

पूरे देश में 'भारत' ब्रांड नाम के तहत ' एक राष्ट्र, एक उर्वरक' की शुरुआत से कम लागत पर उर्वरकों की उपलब्धता आसान हो गई है। यह कृषि पद्धति में आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि को इंगित करता है। इस क्षेत्र को अब राजनीतिक समाधानों की दृष्टि के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।

अब, भारतीय कृषि जनसंख्या-संचालित क्षेत्र के स्थान पर उपभोग-संचालित क्षेत्र बन गई है। भारतीय किसान बहु-कुशल हो गए हैं और छोटे खेत बहुक्रियाशील हो गए हैं। भारत का भविष्य के दृष्टिकोण खेती के टिकाऊ तंत्र की ओर लौटना है, उदाहरण के लिए, मोदी सरकार द्वारा मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, डेयरी, बागवानी, पर्ल और वीड़ फार्मिंग जैसे संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्राकृतिक खेती की पहल की गई है।

नारी शक्ति (महिला सशक्तीकरण)

सभ्यता में महिलाओं को उच्च सम्मान दिया गया है और इसका प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में महिला पात्रों, देवियों के प्रति हमारी श्रद्धा में मिलता है, जिन्हें हमारे मंदिरों और ग्रंथों में 'शक्ति' स्वरूप में बताया गया है। मोदी सरकार ने शासन में आने के बाद से ही महिलाओं को शक्ति अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि देश के सम्मान और विकास के साथ-साथ उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए।

इसको देखते हुए केन्द्र सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' पारित किया जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए 'मिशन शक्ति' नामक एक व्यापक योजना शुरू की गई, इसने महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों को संबोधित किया।

मोदी सरकार की पहल से महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है। इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार के लिए भी कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, देश भर में 10,000 से अधिक जन औषिधि केन्द्रों के माध्यम से 'सुविधा' नामक ऑक्सी-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन केवल 1 रुपये में उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएम-आवास योजना के तहत बनाए गए 4 करोड़ घरों में से 75 प्रतिशत घर या तो पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के स्वामित्व में हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के भविष्य में महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान है और सभी क्षेत्रों में योगदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हमें प्रगति की राह पर ले गया है। महिलाओं की स्थिति को पीड़ित मानसिकता से नहीं, बल्कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और विकास के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखने के दृष्टिकोण से एक आदर्श बदलाव आया है।

परिवार लक्षित अधिकांश योजनाओं में लाभार्थियों के केंद्र में महिलाएं होती हैं, जो दर्शाता है कि घर के साथ-साथ परिवार की प्रगति की कुंजी भी महिलाओं के पास है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए स्वच्छता के महत्व को समझते हुए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जिसके तहत सभी घरों में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। साथ ही, सरकार ने पीएम-उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिये।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के बाद अब आगे का उद्देश्य एक ऐसा व्यवस्था विकसित करना है जो 'महिला नेतृत्व वाले विकास' के युग की शुरुआत करता है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने पीएम मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया शुरू की है। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में मदद करना है। 2024 में स्टैंडअप इंडिया के लाभार्थियों में 84 प्रतिशत से अधिक महिलाएं थीं और मुद्रा योजना के तहत 68 प्रतिशत से अधिक महिला उद्यमी थीं।

इस प्रकार, आज सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान से लेकर पंचामृत लक्ष्यों तक कई पहल शुरू की हैं, हालांकि इन पहलों में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए 'सबका प्रयास' की आवश्यकता है जो हमें 'विकसित भारत' की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का अधिकतम स्तर तक पालन करने और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है, जो हमें 2047 तक एक 'विकसित राष्ट्र' के सपने को साकार करने में मदद करेगा।

आगे के पृष्ठों में हम अपने सुधी पाठकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों को प्रकाशित कर रहे हैं, जो विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मोदी-सरकार द्वारा की गई विकासात्मक पहलों के बारे में गहरी जानकारी देती हैं। →

गरीब कल्याण मोदी की गारंटी

- मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबी में 17.89 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें भारत 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81.35 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क खाद्यान्न की सुविधा मिली
- पी.एम.ए.वाई के तहत 4 करोड़ से अधिक नए घर बनाए गए, जिनमें 75 घरों का स्वामित्व महिलाओं को मिला
- 31 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी कर लगभग 6 करोड़ लोगों को मिला निःशुल्क इलाज
- जल जीवन मिशन ने 11.09 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए, जिससे जीवन में आसानी बढ़ी और सामाजिक स्थितियों में बदलाव आया।

सम्मान की गारंटी

- मोदी सरकार ने स्वच्छ भारतीय ग्रामीण के अंतर्गत 11.45 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है और स्वच्छ भारत-मिशन-शहरी के तहत 100 ओ.डी.एफ. कवरेज किया गया है।
- मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 12.46 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदा करके महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सौभाग्य योजना के जरिए 2.6 करोड़ से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सशक्त बनाया है
- मोदी सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी पहल से अप्रैल, 2023 तक क्रमशः 16 करोड़, 34 करोड़ और 5 करोड़ से अधिक नामांकनों के साथ-साथ एक समग्र सामाजिक सुरक्षा चक्र स्थापित कर रही है
- मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय के तहत सामाजिक कल्याण के लिए बजट आवंटन को 2013-14 से 2023-24 के बीच 200% से अधिक बढ़ाया है

आर्थिक सशक्तीकरण की गारंटी

- पीएम-स्वनिधि योजना ने 61 लाख से अधिक विक्रेताओं की मदद की, जिन्हें 10,716 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया, जिससे असंगठित क्षेत्र की कोविड महामारी के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता हुई।
- जैम ट्रिनिटी (जन धन आधार मोबाइल) के माध्यम से 34 लाख करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) कर भ्रष्टाचार समाप्त, बिचौलिये खत्म
- मोदी सरकार ने पीएम जन-धन योजना के माध्यम से ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 50 करोड़ जन-धन बैंक खातों के साथ, अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया है ▪

अमृत पीढ़ी की
नई उड़ान

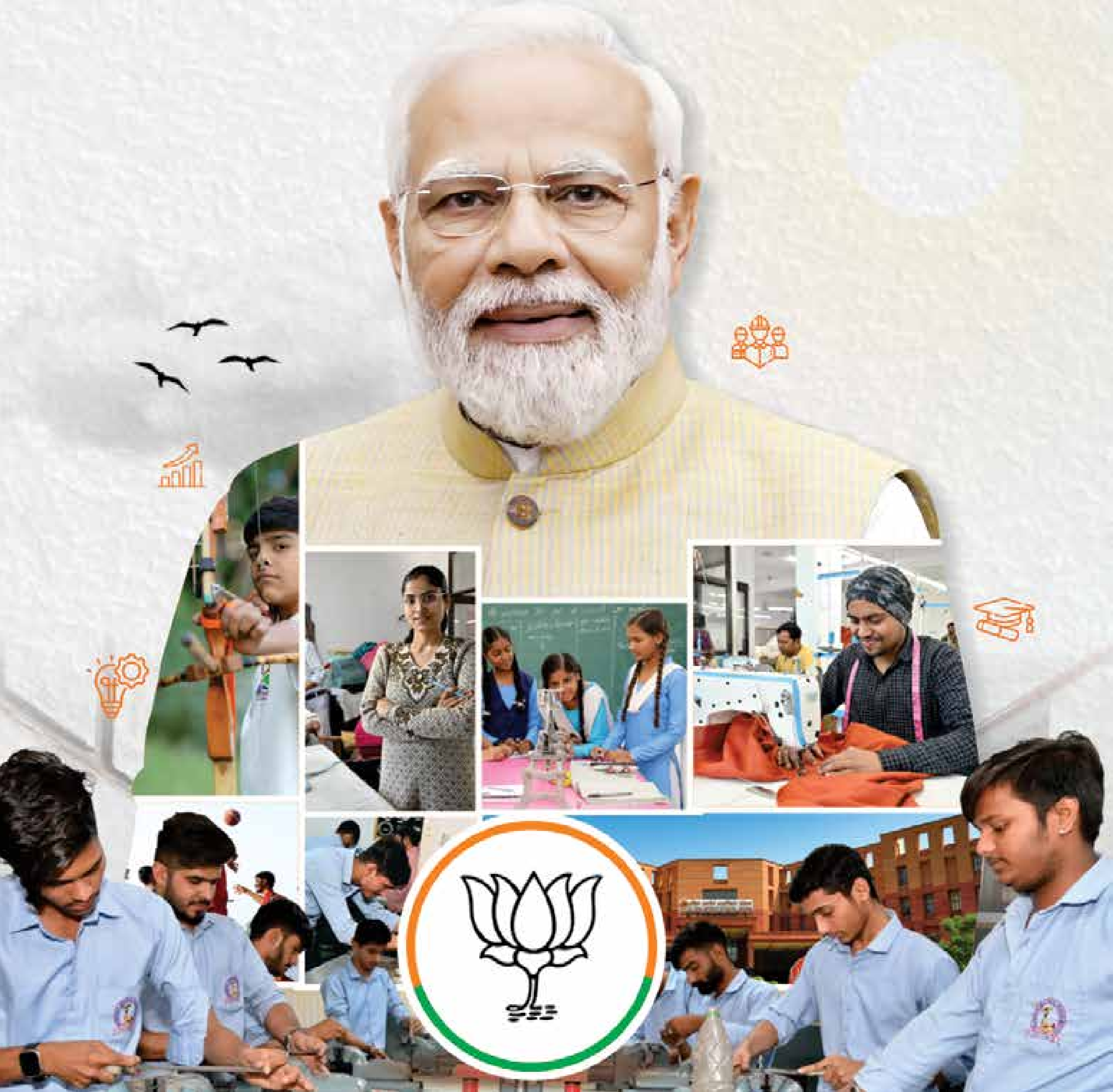

अमृत-पीढ़ी के लिए सुनिश्चित की शिक्षा से समृद्धि

शिक्षा क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास

- 2024-25 में शिक्षा मंत्रालय को 1,20,627 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो यूपीए के 2013-14 के बजट से 50% से अधिक है
- यूपीए (2013-14) की तुलना में 2021-22 में उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात में 23.47% की वृद्धि हुई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति: 2020

- परिवर्तनकारी सुधार 1986 की 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव
- समग्र शिक्षा हेतु शिक्षकों की निष्ठा
- विद्यांजलि वॉलंटियर आधारित मार्गदर्शन
- रचनात्मक संयोजन के साथ विषयों का लचीला पाठ्यक्रम; एकाधिक प्रवेश/निकास के विकल्प
- क्रेडिट का एकेडमिक बैंक शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को डिजिटली स्टोर करना
- निपुण भारतः आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता

प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता

- 2016 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) शुरू की गई जो 'एक देश, एक परीक्षा, एक योग्यता' सुनिश्चित करती है
- एकल-खिड़की अवसर प्रदान करके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश को आसान बनाने के लिए 2022-23 में कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) शुरू की गई

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आईटीआई) का विकास

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आईटीआई) में 1.5 गुना की बढ़ोतरी

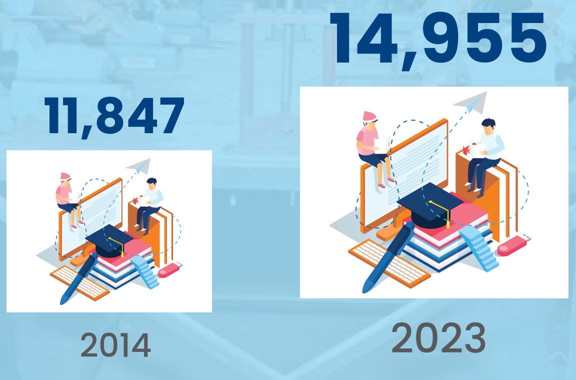

- 390 विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में विस्तार किया गया
- 2014 के बाद से 5,700 से अधिक नए कॉलेज खुले हैं, यानी प्रतिदिन लगभग 2 नए कॉलेज
- MBBS सीटों में 112% और PG सीटों में 127% की बढ़ोतरी

अमृत-पीढ़ी के कौशल विकास एवं रोजगार के नए अवसर प्रदान किये

बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि

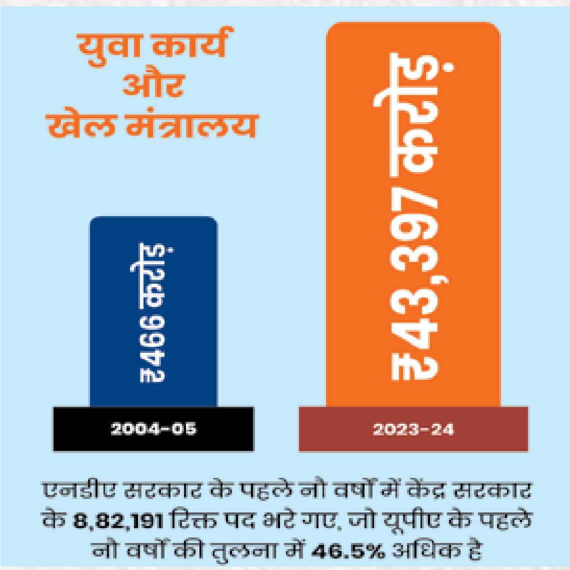

डायरेक्ट जॉब इंडेक्स

- अप्रैल, 2020 से 18-28 वर्ष की आयु वर्ग के 2.09 करोड़ से अधिक युवाओं को EPFO में जोड़ा गया
- कैपिटल गुड्स सेक्टर में कौशल, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यबल को बढ़ाने के लिए स्किल काउंसिल द्वारा स्किल लेवल 6 में 46 क्वालीफिकेशन पैकेज बनाये गये
- नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स ने जनवरी, 2021 में 1,925 से जनवरी 2022 में 2,716 की अप्रत्यक्ष नौकरी संकेतक की 41% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई

इनडायरेक्ट जॉब इंडेक्स

- 2021-22 में भारत का माल निर्यात रिकॉर्ड 422 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया
- 2020-21 की तुलना में 2021-22 में इंजीनियरिंग निर्यात 46% अधिक रहा
- 2021-22 में परिधान निर्यात में 30% की वृद्धि देखी गई। यह अनुमान है कि प्रत्येक अतिरिक्त $1 बिलियन परिधान निर्यात 1.5 लाख नौकरियां पैदा करते हैं

भारत को खेलों की बड़ी शक्ति बनाना

TARGET OLYMPIC PODIUM SCHEME (TOPS)

- योजना का लक्ष्य एथलीटों का चयन कर विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में उनके अनुकूलित प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
- TOPS कोर ग्रुप में 98 एथलीटों की सहायता
- TOPS डेवलपमेंट ग्रुप में 182 एथलीटों की सहायता

खेलो इंडिया योजना

- बुनियादी ढांचे के निर्माण, प्रतियोगिताओं के आयोजन और प्रतिभा को पोषित करने के लिए योजना
- 2024-25 के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए
- 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 36 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र अधिसूचित किए गए

- खेलो इंडिया आयोजनों में 30,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले चुके हैं
- 2,836 करोड़ की कुल स्वीकृत लागत पर 308 नई खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं स्वीकृत (179 पूर्ण)
- 2,400 से अधिक खेलो इंडिया एथलीटों को उनके एथलेटिक विकास के लिए प्रति वर्ष 6,28,400 रुपए आवंटित किए जाते हैं
- राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खेल उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए 61 पदकों के साथ भारत का उल्लेखनीय प्रदर्शन
- एशियाई खेलों के 2023 संस्करण में 107 पदक जीते
- भारत ने 141वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी की, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2030 युवा ओलंपिक के भारत में आयोजन की रुचि की घोषणा की

पूर्वोत्तर में हो रहा खेल जगत का विकास

- 643.34 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत लागत पर मणिपुर में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है
- खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाएं आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही हैं ■

अन्नदाताओं की समृद्धि
मोदी की गारंटी

किसानों के हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया

किसान सम्मान निधि

- 2019 में शुरुआत, किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की सहायता
- लगभग 12 करोड़ किसान हो रहे लाभान्वित

फसल बीमा योजना

- 2016 में शुरुआत, फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता
- लगभग 57 करोड़ किसान पंजीकृत
- 1.55 लाख करोड़ से अधिक का निपटारा

जैविक उर्वरकों पर फोकस

- गोबरधन संयंत्रों से जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) के लिए 1451.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए
- 2015 से सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड यूरिया पर 100% नीम कोटिंग लागू किया गया
- खाद व कीटनाशकों के ड्रोन द्वारा छिड़काव पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- मृदा में पोषक तत्वों के उपयोग में वृद्धि के लिए 2014-15 में योजना की शुरुआत
- किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए
- DAP उर्वरक के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 1200 रुपये प्रति बैग की गई जो कि 140% की वृद्धि है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बावजूद हमारे किसानों को DAP उर्वरक के बैग बढ़ी हुई कीमतों के आधे दाम पर मिले, क़ीमतें नहीं बढ़ी तथा स्थिर रहीं

किसान क्रेडिट कार्ड

- कृषि यंत्रों की खरीद और अन्य कृषि खर्चों हेतु 7.45 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए और किसानों को कर्ज प्राप्ति के लिए साहूकारों से मुक्ति दिलाई
- मत्स्य, डेयरी व सम्बद्ध क्षेत्रों को भी किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत शामिल किया गया

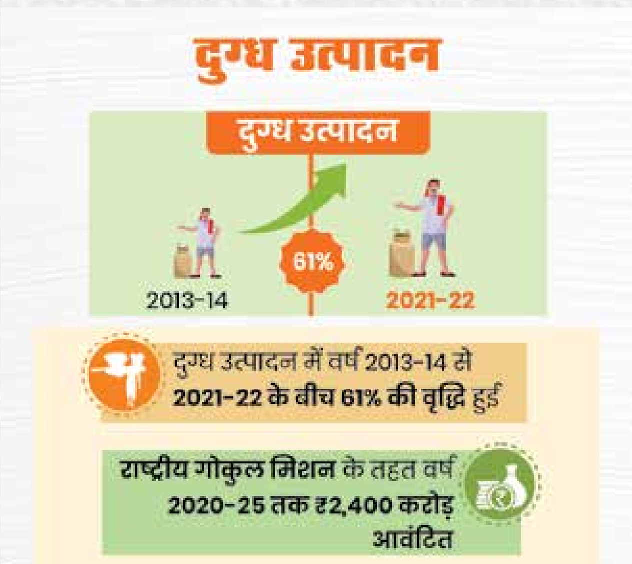

मत्स्य पालन

- Blue Revolution की शुरुआत कर पूरा फोकस केन्द्रित करने के लिए Department of Fisheries
- वर्ष 2015 से मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में 38,572 करोड़ रुपए का निवेश

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- 1.25 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित
- 2015 से 83 लाख हेक्टेयर से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज
- वर्ष 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपए आवंटित

ई-नाम

- मौजूदा बाजारों को ई-प्लेटफार्म के माध्यम से एकीकृत करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया
- ई-नाम के माध्यम से अब 1,361 मंडियां को जोड़ा गया
- 1.78 करोड़ किसान पंजीकृत

संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व

- ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ गावों का सर्वेक्षण और मैपिंग
- अप्रैल 2020 में हुई शुरुआत
- अब तक 1.6 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कार्ड बनाए गए

- 97,200 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड शीर्षक विलेख जारी किये गए
- सितम्बर, 2022 तक 2.81 लाख गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हुआ

कृषि अवसंरचना कोष

- कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा
- योजना के कार्यान्वयन के 3 साल से भी कम समय में 38,326 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसने कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 30,030 करोड़ रुपये के कुल ऋण के साथ 50,988 करोड़ रुपये जुटाए हैं
- कृषि इन्फ्रा परियोजनाओं ने 5.8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जबकि सालाना 3.7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 46.3 लाख मीट्रिक टन बागवानी संबंधी उत्पादन की बचत की है और किसानों को 20-25% की सीमा तक बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की है

पीएम-प्रणाम

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में 'पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड ऐमेलिओरेशन ऑफ मदर अर्थ (पीएम-प्रणाम)' को मंजूरी दी
- इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है

खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार

- मेगा फूड पार्क की संख्या वर्ष 2014 में 2 से बढ़कर वर्ष 2023 में 24 हुई
- किसान उत्पादक संगठन के लिए वर्ष 2027-28 तक लगभग 6,800 करोड़ की बजट मंजूरी

कृषि निर्यात में वृद्धि

- भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में 25% की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ, निर्यातक की भूमिका प्राप्त की है
- भारत का कृषि निर्यात अब 42% से अधिक की वृद्धि के साथ 4 लाख करोड़ हो गया है
- वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपया कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित

- किसानों के लिए वर्ष 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा
- 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, जो 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) में किया जा रहा है

श्री अन्न

- श्री अन्न (मोटे अनाज) को मोदी सरकार के प्रयास से वैश्विक बाजार में नई पहचान मिली
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया
- किसानों द्वारा एशिया में बाजरा का 80% और दुनिया में 20% उत्पादन किया गया ■

वीमेन लेड डेवलपमेंट की ओर
बढ़ते कदम

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया

युद्ध क्षेत्र में नारी शक्ति

- सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी आयोग
- तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों का प्रवेश
- सैनिक स्कूलों एवं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रवेश

महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए

- नाबालिगों से बलात्कार के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान कर न्यूनतम सज़ा को बढ़ाकर 20 साल किया
- तीन तलाक पर कड़े कानून बनाए
- अनुच्छेद 35ए ख़त्म कर जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को उनके खोये हुए अधिकार वापस दिलाये
- महिलाओं की विवाह योग्य आयु अब 21 वर्ष

नारी शक्ति के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित की गई

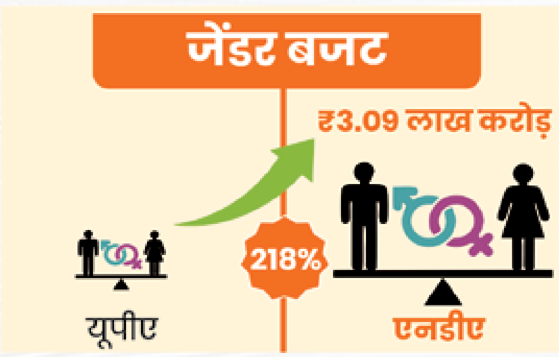

2024-25 में लिंग अंतर को कम करने के लिए **जेंडर बजट को 3.09 लाख करोड़ रुपये आवंटित** किए गए। यह **यूपीए के आवंटन (2013-14) से 218%** अधिक है

भारत में पहली बार **प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं**

मातृ वंदना

- पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 4.18 करोड़ से अधिक मुफ्त प्रसवपूर्व जांच की गई
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3 करोड़+ महिलाओं को 14,888 करोड़+ रुपए की सहायता
- पेड मैटरनिटी लीव 12 से 26 सप्ताह की गई

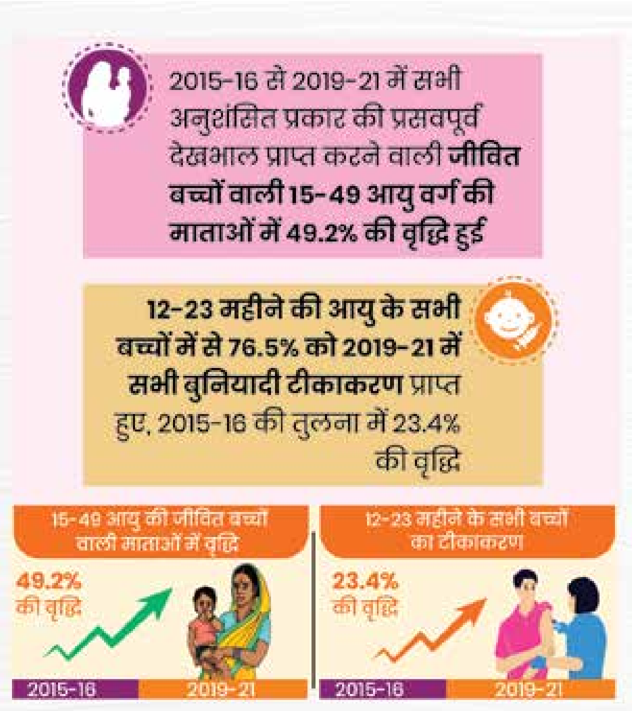

- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) मातृ एवं नवजात मृत्यु को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क उपचार प्रदान करता है
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव की हकदार है
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है

- 2019-21 में 15-24 आयु वर्ग की 77.6% मासिक धर्म वाली महिलाएं स्वच्छ मासिक धर्म सुरक्षा का उपयोग कर रही थीं, जो 2015-16 की तुलना में 34.72% की वृद्धि है
- 1 में 50 करोड़+ जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैड वितरित
- 2014-16 की तुलना में 2018-20 में मातृ मृत्यु दर में 25% से अधिक की गिरावट (प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 तक)

स्वच्छता व सुरक्षा

- 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया
- शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को खुले में शोच से मुक्ति मिली
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत 75% गांव अब ODF+ हुए

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- 10 करोड़+ स्वच्छ ईंधन युक्त रसोइयां
- महिलाओं को धुएं की घुटन से मिली मुक्ति

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण व जीवन में सुगमता

सुकन्या समृद्धि

- फरवरी, 2024 तक 3.77 करोड़ से अधिक खाते पंजीकृत
- 2.13 लाख करोड़ से अधिक धनराशि जमा
- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दर 8.2% है

बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा

- पीएम जन-धन योजना के तहत 50 करोड़+ व्यक्तियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया
- कुल खाताधारकों में 55% महिलाएं

उद्यमिता को बढ़ावा दिया

- जनवरी, 2024 तक पीएम मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत 46.03 करोड़ में से लगभग 68% महिला लाभार्थी
- जनवरी, 2024 तक 2.15 लाख स्टैंड अप इंडिया योजना खातों में से 84% महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए

लखपति दीदी

- एसएचजी के माध्यम से 1 करोड़+ महिलाएं बनी लखपति दीदी
- नमो ड्रोन दीदी के तहत 1,000 ड्रोन्स का वितरण
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7.68 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण

पक्के घर की सौगात

- पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण किया गया
- पीएम आवास योजना-ग्रामीण के 72% घरों में महिलाओं का स्वामित्व

सौभाग्य योजना

- केरोसिन वाले लैंप अब बीते दिनों की बात
- 100% घरों तक बिजली पहुंचाई गई

जल जीवन मिशन

- घर-घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाया गया
- 14 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए गए ■

मजबूत अर्थव्यवस्था से
विकसित भारत

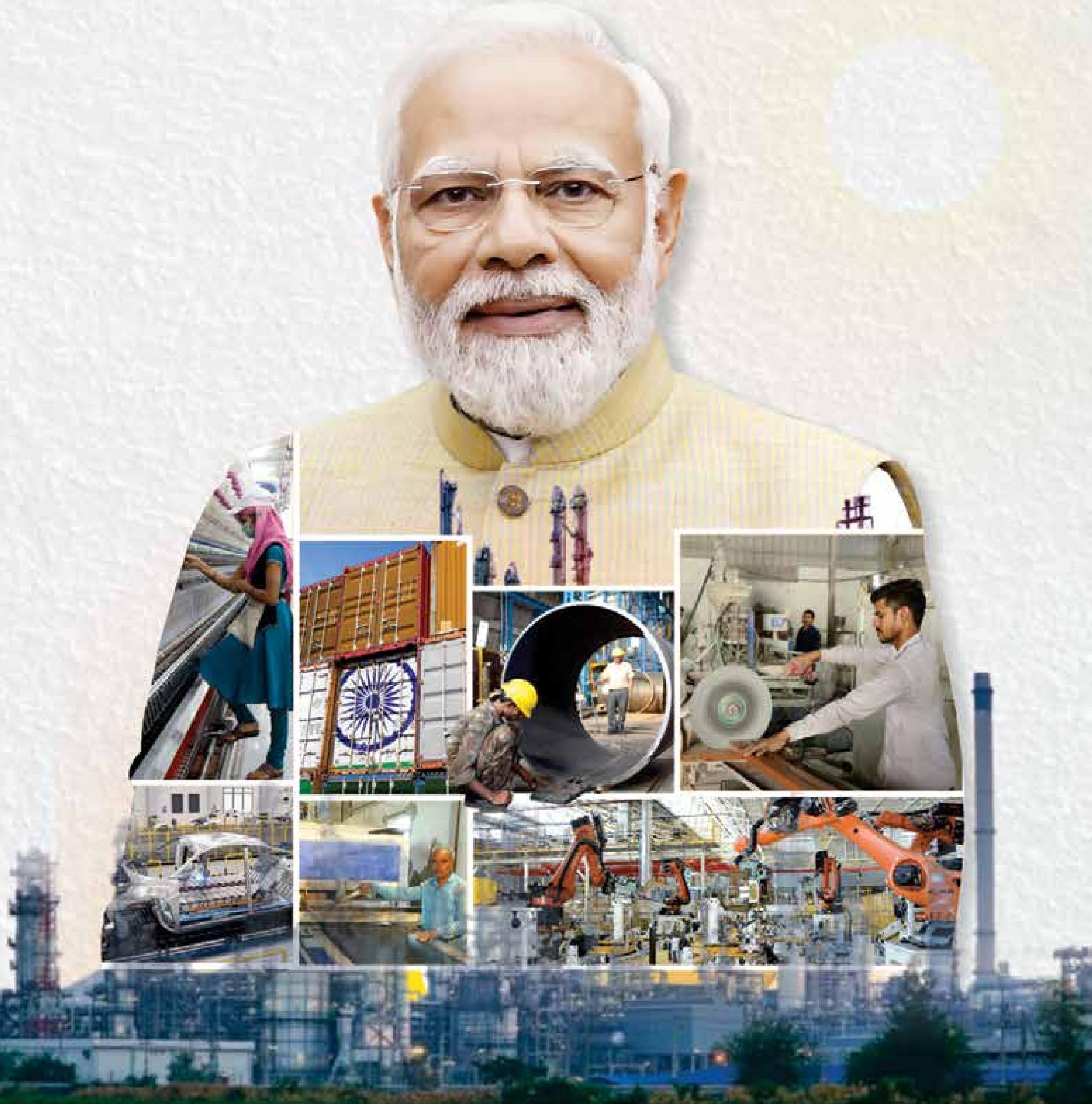

ढांचागत रिफॉर्म

- 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री की गई
- प्रति व्यक्ति आय दोगुना से भी ज्यादा होकर 1.97 लाख रुपये हुई
- सख्त कार्रवाई के कारण एनपीए और आर्थिक अपराधों में तेज गिरावट, 6.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक फंसे कर्ज की प्राप्ति हुई

डीबीटी से लीकेज को हटाया

- 2.73 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई
- 4.2 करोड़ नकली एवं जाली राशन कार्ड (2013-2021) को हटाया
- ग्रामीण विकास मंत्रालय मे जाली/ फर्जी/अपात्र लाभार्थियों को हटाया

एमएसएमई क्षेत्र के लिए सुधार

- मुद्रा योजना के तहत 25.5 लाख करोड़ रूपये के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत
- एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का एमएसएमई ऋण डूबने से बचाया जा सका

यूपीआई से कायाकल्प

- **UPI और RuPay :** दुनिया की सबसे सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम
- यूपीआई से विश्व के 46% डिजिटल लेन-देन अब भारत मे हो रहे हैं
- आज 7 देशों में यूपीआई सुविधा उपलब्ध

उद्योगों को मिला समर्थन

- कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी स्वीकृतियों की संख्या 14 से घटाकर सिर्फ 3 हुईं
- कॉर्पोरेट टैक्स की दरें 30% से घटाकर 22% की गईं और कुछ नई कंपनियों के लिए 15%
- पीएलआई स्कीम से 14 सेक्टर में उद्योगों को 1.97 लाख करोड़ रुपये मूल्य के प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए

स्टार्टअप इंडिया

- भारत में $347 अरब अमरीकी डॉलर के 100 से अधिक यूनिकॉर्न
- वैश्विक स्तर पर हर 10 मे से 1 यूनिकॉर्न भारत में
- विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना भारत

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

- सबको बैंकिंग, सबको सुरक्षा
- 15 अगस्त 2014 को शुरुआत
- 50 करोड़+ खाते खोले गए
- 34.26 करोड़ रुपे कार्ड जारी
- औसत जमा राशि 4,066 रुपये
- कुल 2.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

- पोर्टल ने 4.91 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वार्षिक खरीद दर्ज की
- ऑर्डरों की संख्या 1 करोड़ के पार, जिसमे 55% ऑर्डर मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्योग से
- जेम (GEM) पर 8 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्योग सेवा प्रदाता पंजीकृत ■

राष्ट्रीय सुरक्षा
मोदी की गारंटी

आत्मनिर्भर भारत' पहल से 101 रक्षा वस्तुओं की सूची में तोप, असॉल्ट राइफल, परिवहन विमान आदि के भारत में निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

- डीआरडीओ के अलावा सरकार भी निजी क्षेत्र में और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए विदेशी साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिये सह-उत्पादन पर जोर दिया गया है
- रक्षा गलियारे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आने वाले 5 वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है
- शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए देश में 'राष्ट्रीय समर स्मारक' की स्थापना की गई
- वन रैंक-वन पेंशन की मांग पूरी— दशकों पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करके सैनिकों को सम्मान दिया गया

रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की गारंटी

- 2023-24 का रक्षा बजट लगभग 6 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।
- सीडीएस के पद के निर्माण से सैन्य बलों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना आसान हुआ है
- बुलेट प्रूफ जैकेटों की मांग पूरी— सेना द्वारा वर्ष 2009 में की गई बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद को स्वीकृति दी गई
- सेना के लिए राफेल सहित अन्य अत्याधुनिक हथियारों की खरीद को स्वीकृति दी गई अब हम स्वदेशी हथियार बनाने की क्षमता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
- वायुसेना के लिए 83 भारत निर्मित तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए स्वीकृति
- भारतीय सेना को 2020 में चिनूक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिला, भारत के पास 15 हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, तोप और बस्तबंद गाड़ियों के अलावा भारी मशीनरी ले जाना आसान हुआ

सौहार्द और सम्मान की गारंटी

- कश्मीर में अब हिंसा में 80% की गिरावट आई है, नागरिक मौतों में 89% की कमी आई और 6,000 से अधिक आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया
- 21 अक्टूबर, 2018 को हमारी मातृभूमि की अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया

सैनिकों को बेहतर सुविधाओं की गारंटी

- युद्ध में घायल सैनिकों के लिए सरकारी आवास की सुविधा को 3 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करने की मंजूरी
- अब शहीदों के परिजन या दिव्यांग सैनिकों को 4 गुना आर्थिक मदद, 2 से 8 लाख रुपये हुई राशि की गई

उपकरणों की उपलब्धता एवं इंफ्रास्ट्रक्चर

- अब, देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब-करीब 4 गुना कर दिया गया है
- देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, तोए, गोला-बारूद, टैंक, मिसाइल, एंटी-टैंक माइन्स एवं अन्य उत्पादों को मित्र देशों को निर्यात हेतु अनुमति मिली
- अब, जमीन से हथा में मार करने वाले आकाश मिसाईन, हवा से हवा में मार करने वाली 'अस्त्र' मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 'नाग' एवं 'ब्रह्मोस' निर्यात के लिए तैयार हैं
- सीमा सड़क संगठन की 724 करोड़ रुपए की 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से सेना की दूर-दराज़ के इलाकों में पहुंच आसान हुई ■

सांस्कृतिक कायाकल्प
मोदी की गारंटी

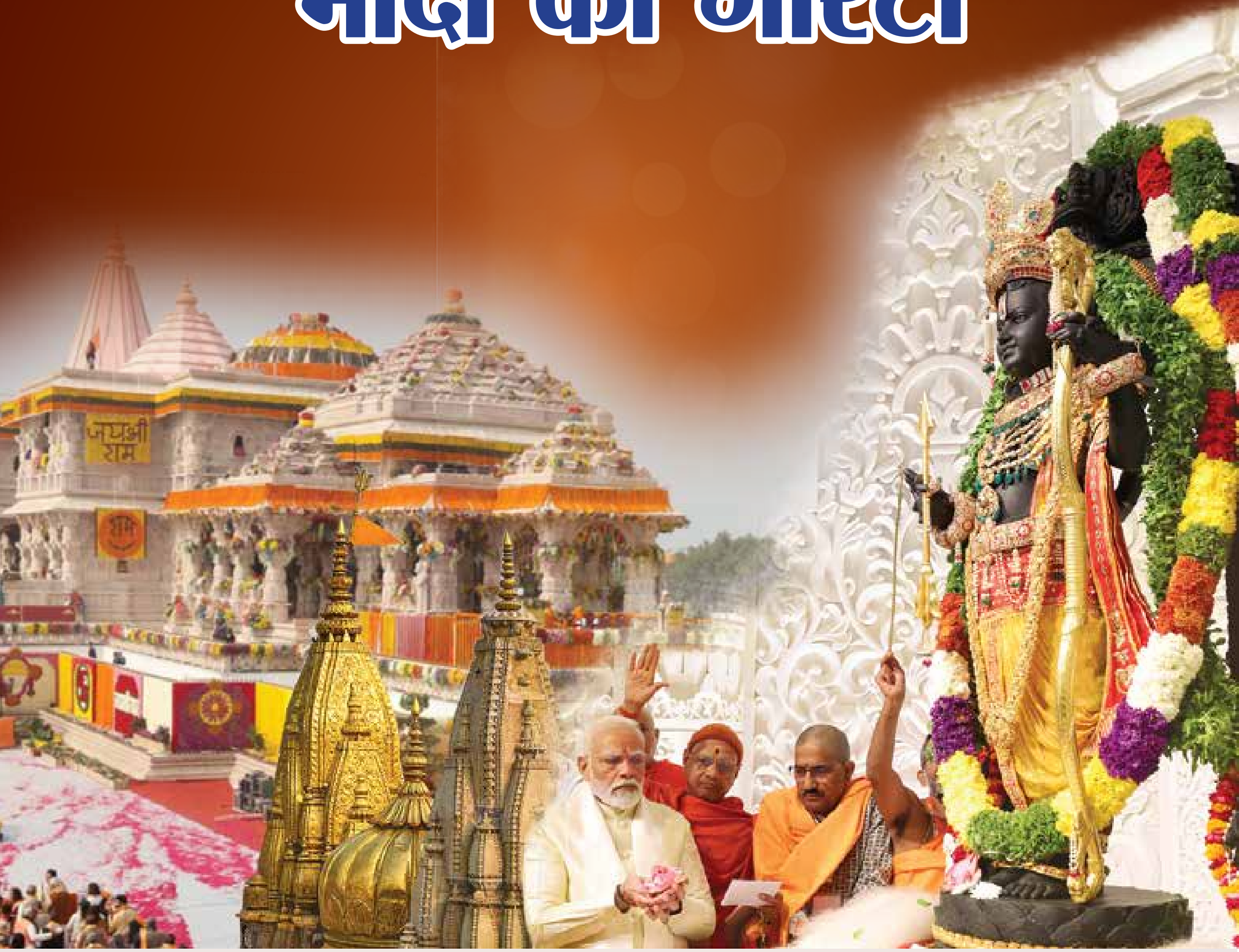

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी, 2024 को भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ और देश से लेकर विदेश तक हर्षोल्लास का वातावरण छाया रहा
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अबू धाबी के प्रथम हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो सम्पूर्ण मानवता के एक सांस्कृतिक मील के पत्थर का प्रतीक है। यह मोदी सरकार की पहल और भारत और यू.ए.ई. के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने से संभव हुआ
- दिसंबर, 2021 में 900 करोड़ रुपए के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उदघाटन किया गया, जिससे घरेलू पर्यटकों की संख्या 2018 में 60.95 लाख से बढ़कर 2022 में 7.16 करोड़ हो गई
- उत्तराखण्ड चारधाम महामार्ग विकास परियोजना को जोड़ने के लक्ष्य के साथ 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत

- उज्जैन में 856 करोड़ रुपए की कुल लागत से 'महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर' का उद्‌घाटन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, वहां वार्षिक श्रद्धालुओं की संख्या तीन गुना बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई
- 'भारत रत्न' बाबसाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच पवित्र स्थलों का 'पंचतीर्थ' के रूप में विकास

सांस्कृतिक सौहार्द की गारंटी

- भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' और गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने से समाज एवं संस्कृति के लिए प्राण न्योछावर करने की समृद्ध परंपरा को सम्मान मिला
- मोदी सरकार ने असम में, मां कामाख्या देवी कॉरिडोर के निर्माण की योजना का अनावरण किया, जो सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है
- मोदी सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रतीक 'सेंगोल' को नए संसद भवन में स्थापित कर भारतीय विरासत के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया
- मोदी सरकार ने तमिलनाडु के साथ काशी और गुजरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, जिसका उदाहरण 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम और 2022 में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम है
- जून, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिल भाषा के वैश्विक महत्व और वैश्विक मंच पर भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में एक तमिल अध्ययन पीठ की स्थापना की घोषणा की
- मोदी सरकार ने देश की पुरातन विरासत को सुरक्षित करने की दिशा में कई महत्वूर्ण कदम उठाये है। मोदी सरकार गैरकानूनी तरीके से विदेश ले जाई गई प्राचीन कलाकृतियों को लगातार वापस लाने में तत्परता से जुटी हुई है, विभिन्न देशों से 238 कलाकृतियों को वापस लाया गया है
- कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शारदा मंदिर का उद्‌घाटन अंतरधार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक कायाकल्प का एक बड़ा उदाहरण है
- 2014 में यू.एन.जी.ए. में पी.एम. श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्ताव के कारण 2015 से प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और 2023 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक योग सत्र का नेतृत्व किया, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
- 2019 में उद्‌घाटन किए गए करतारपुर कॉरिडोर में दिसंबर, 2022 तक तीर्थयात्रियों की संख्या 1.3 लाख देखी गई है, जिसकी सुरक्षा के लिए 18.6 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं
- कंबोडिया में हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार, वैश्विक सभ्यता के मध्य के संबंधों को संरक्षित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह पहल राष्ट्रीय सीमाओं से परे सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है
- ओंकारेश्वर, श्रीशैलम, बैद्यनाथ धाम, कालिका माता मंदिर और वाराणसी में रिवर क्रूज़ जैसी विकास परियोजनाएं सांस्कृतिक बहाली और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए मोदी सरकार के समर्पण को दर्शाती हैं, जो यूपीए शासन में कहीं नहीं देखी गयी थी

- आदि महोत्सव द्वारा भारतीय जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया। आदि महोत्सव 2024 में 300 से अधिक स्टालों के साथ 1,000 कारीगरों ने भाग लिया, जो उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है
- मोदी सरकार के अथक प्रयासों से अफगानिस्तान से सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ साहिब के तीन 'सरूप' वापस भारत लाए गए हैं
- पवित्र धार्मिक स्थल श्री हरमंदिर साहिब को अब विदेश से भी श्रद्धालु लंगर और सेवा के लिए दान कर सकते हैं। इसके लिए एफ.सी.आर.ए. (FCRA) के नियम में अहम बदलाव कर इसका पंजीकरण किया है।
- मोदी सरकार द्वारा प्रति माह 5 हजार से अधिक लोगों को मुफ्त खाना खिलाने वाली धार्मिक संस्थाओं को G.S.T. में राहत दी है। ■

सुशासन राष्ट्र के विकास की कुंजी है

- जन-धन, आधार और मोबाइल (जैम ट्रिनिटी) के एकीकरण से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारा नकद हस्तांतरण प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया, जिससे लाभार्थियों को त्वरित लाभ सुनिश्चित हुआ एवं फर्जी लाभार्थियों की पहचान द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार कम हुआ। अब तक डीबीटी के माध्यम से लगभग 35.38 लाख करोड़ रुपये की सहायता पहुंचाई जा चुकी है।

- पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (PDI) जैसे UPI आधार, कोविन ऐप, फास्टैग, डिजीलॉकर, भारत बिल पे आदि की सफलता ने भारत को डिजिटल लोकतंत्र के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। कोविन ऐप से न केवल भारतीय, अपितु दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हुए। नास्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार PDI के महत्वपूर्ण योगदान से भारत 2030 तक 8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकेगा।
- सामाजिक न्याय व आर्थिक स्वावलम्बन का आधारस्तंभ अपने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बल प्रदान करते हुए सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू MSME से 25% खरीद करने का आदेश दिया जिसमें 3% महिला व 4% एससी/एसटी स्वामित्व वाले MSME हेतु आरक्षित है। एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसएमई से 2013-14 में कुल खरीद 80.45 करोड़ रुपए था जो 2022-23 में बढ़कर 1,545.36 करोड़ रुपए हो गया। इसी के साथ कृषि, कुटीर उद्योगों, लोक कलाओं एवं विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ।

- जीएसटी द्वारा 'एक देश, एक बाजार, एक कर' का स्वप्न पूर्ण करते हुए सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार किया गया। जीएसटी के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा मासिक घरेलू खर्चों पर 4% की बचत हुई है। सरकार द्वारा किये गये व्यापक कर सुधारों एवं सुगम ऑनलाइन कर भुगतान प्रणालियों के कारण आज देश में 9.37 करोड़ आयकर दाता हैं, जो 2014 में मात्र 5.26 करोड़ थे। जीएसटी के द्वारा कुख्यात इंस्पेक्टर राज का खात्मा सुनिश्चित हुआ।

- व्यापार एवं निवेश की सुगमता हेतु नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था द्वारा निवेशकों को देश के 28 केंद्रीय विभागों एवं 20 राज्यों के विभागों द्वारा एकीकृत मंजूरी दिलाने की व्यवस्था है। सरकार के व्यापक सुधारों के चलते विश्व बैंक के ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में भारत छलांग लगाकर 142वें स्थान से 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इस पोर्टल पर नवंबर, 2023 तक 2,55,000 से अधिक स्वीकृतियां दी गई हैं।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से बढ़ी सार्वजनिक खरीद प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और गति**— 2016 में इसके शुभारंभ के पश्चात् अब तक इस पोर्टल पर कुल 79 लाख करोड़ रुपए के 2.1 करोड़ ऑर्डर हुए एवं सरकारी विभागों के 80 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।
- मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवा को आधुनिक बनाना, सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और उभरती जरूरतों के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण देना है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों

(2020-21 से 2024-25) में लगभग 46 लाख कर्मचारियों को शामिल करने का लक्ष्य है। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 28 लाख शिक्षार्थियों ने नामांकन किया है एवं 35 करोड़ प्रशिक्षण मिनट्स लोगों द्वारा प्राप्त किया गया।

- स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.4 करोड़ युवा प्रशिक्षित हुए तथा 54 लाख युवाओं ने पुनर्प्रशिक्षण से विशेषज्ञता हासिल किया। केंद्र सरकार के 20 केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों द्वारा व्यापक पैमाने पर छोटे एवं बड़े कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस योजना के तहत 3000 नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संस्थान खोले गए हैं।
- विश्वस्तरीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं नवाचार इकोसिस्टम के विकास के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थान— 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), 15 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) खोले गए हैं। इसके अलावा देश भर में 390 विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं।

- 'बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ' योजना से देश में आया व्यापक परिवर्तन। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी एवं गणित पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का 43% नामांकन है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। भारत की आधी आबादी के इस योगदान से भारत विश्व का टैलेंट पूल बन रहा है।

- स्टार्टअप इंडिया से भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक सिस्टम। भारत के सवा लाख से अधिक स्टार्टअप्स, 110 यूनीकॉर्न द्वारा 12 लाख लोगों को मिला। स्टार्टअप्स ने नवाचारों के बल पर 12,000 पेटेंट्स हासिल किये। स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के कारण आज भारत, विदेशी निवेशकों का पसंदीदा देश बन गया है।

- लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता MyGov पोर्टल भारत के नागरिकों के लिए जुड़ाव का मंच है। 2014 में स्थापित यह पोर्टल नीति निर्माण और जनता की राय के लिए विभिन्न सरकारी निकायों और मंत्रालयों के साथ जुड़कर काम करता है। वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक नागरिक इसके पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने मोदी सरकार के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया है।
- 'सबका साथ, सबका विकास' को सुनिश्चित करता आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) का लक्ष्य देश भर के 112 सबसे अविकसित जिलों में जल्दी और प्रभावी ढंग से बदलाव लाना है। क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को कम करने और संतुलित विकास को बढ़ाने के लिए, 112 अविकसित जिलों में तेजी से बदलाव लाने के लिए 2018 में इसे शुरू किया गया। इससे स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक जैसे मापदंडों पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इनका प्रदर्शन चैंपियंस ऑफ चेंज' के नाम से प्रकाशित किया जाता है।
- स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.4 करोड़ युवा प्रशिक्षित

हुए तथा 54 लाख युवाओं ने पुनर्प्रशिक्षण से विशेषज्ञता हासिल किया। केंद्र सरकार के 20 केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों द्वारा व्यापक पैमाने पर छोटे एवं बड़े कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस योजना के तहत 3000 नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संस्थान खोले गए हैं।

- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से देश बन रहा विश्वस्तरीय मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हब, जिससे देश लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स में शीर्ष देशों की सूची में आ सके। देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 60 सरकारी व सहयोगी एजेंसियों, 37 निर्यात प्रोत्साहन कौंसिल तथा 500 प्रमाणन संस्थाओं की भागीदारी के मकड़जाल को खत्म करने के क्रम में 15 से अधिक मंत्रालयों के बीच सूचनाओं एवं रणनीतियों की एक साझी व्यवस्था से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करना है।
- एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए प्रत्येक जनपद से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना है। ओडीओपी पहल ने देश भर के 761 जिलों से कुल 1,102 उत्पादों की पहचान की है, साथ ही निर्यात की बड़ी संभावनाओं के द्वार खुले हैं।
- **शुद्ध ऊर्जा सुलभता एवं आत्मनिर्भरता:** 2010 में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 11 मेगावाट थी जो 2020 में तीन हजार गुना बढ़कर 35 गीगावाट हो गई। भारत में सोलर टैरिफ वित्त वर्ष 2015 के 7.36 रुपए/kWh से जुलाई, 2021 में कम होकर 2.45/kWh हो गया। 'गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी' रैंकिंग में 2014 के 137 से 2019 में भारत की रैंक 22 हो गई। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन द्वारा सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन ईंधन उत्पादित किया जाए।

- मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन-ऑन (एन.एस. एस.ओ.) जन परिचय, ई-प्रमाण और डिजीलॉकर प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रदान करता है। 2022 में लॉन्च किया गया; 7,760 सेवाओं के साथ एकीकृत यह पोर्टल 28.50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं दे रहा है और 90 करोड़ लेनदेनों की सुविधा प्रदान कर चुका है। इसके प्रयोग से अनावश्यक कागज के प्रयोग से पर्यावरण को हानि नहीं होगी, प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग से बचा जा सकेगा।
- भारत में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस) लॉन्च किया गया। 2017 में जारी की गयी यह सुविधा 1,882 से अधिक ई-सेवाओं तक किफायती मूल्य पर पहुंच प्रदान करता है। जनवरी, 2024 तक 407.09 करोड़ के लेनदेन की सुविधा इस पोर्टल द्वारा प्रदान की गई।
- 'रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म' के सिद्धांत पर देश में 11 औद्योगिक गलियारों का विकास हो रहा है। इन गलियारों में औद्योगिक नगरों की स्थापना, तीव्र गति रेल सेवा, मानक वायु सेवा, बंदरगाह, पावर प्लांट्स तथा 8 लेन के एक्सप्रेसवेज का विकास किया जा रहा है, जिसका उदाहरण हमें दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के द्वारा देखने को मिल रहा है।
- मेक इन इंडिया से साकार होते आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र के विकास क्रम में 41 आर्डिनेंस फैक्ट्रियों को विलय कर 7 सरकारी कंपनियों का निर्माण किया गया है। निजी कंपनियों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी द्वारा लड़ाकू विमान, युद्धक आदि बनाने हेतु आमंत्रित किया गया। सृजन पोर्टल के द्वारा

देश के रक्षा एवं अनुसन्धान के क्षेत्र तथा ड्रोन आदि निर्माण में नए स्टार्टअप्स को लगाया जा रहा है।
- वाराणसी, उज्जैन, अयोध्या आदि तीर्थ नगरों के विकास से सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। ऐसे शहरों एवं क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के कारण बड़े स्तर पर लोगों के रोजगार सृजन के साथ सामाजिक सुधार का क्रम प्रारम्भ हुआ। पर्यटन विभाग की तरफ से जारी वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार वाराणसी में रिकॉर्ड 712 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक आए हैं। ■

पर्यावरण संरक्षण
हमारा दायित्व

अथर्ववेद के अनुसार, 'पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके संतान हैं।' भारतीय दर्शन और जीवनशैली हमेशा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की अवधारणा से प्रेरित रही हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से भारत, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस पहल करने वाला अग्रणी देश बना है

- इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) बना व 2014 से अब तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 2300% से अधिक की वृद्धि
- सूर्योदय योजना से 1 करोड़ से अधिक परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं
- उजाला योजना के तहत 36.86 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित
- हाइड्रो कार्बन मिशन की घोषणा
- दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क (2200 मेगावाट से अधिक) राजस्थान के भड़ला में शुरू

- 2070 तक Net-Zero कार्बन उत्सर्जन एमिशन का लक्ष्य
- भारत के पास अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता, चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता और पांचवीं सबसे बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता है
- भारत का पहला कार्बन-न्यूट्रल गांव जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव बना

- पवित्र गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन-2 को 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए स्वीकृत व 38,126 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की गईं
- देश में वन्यजीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों में 34% की वृद्धि
- **प्रोजेक्ट चीता:** विश्व की पहली अंतर-महाद्वीपीय बड़े जंगली मांसाहारी पुनर्वास परियोजना
- 2022 की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी रिकॉर्ड ऊंचाई पर 3167 तक पहुंच गई है
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध के साथ सस्टेनेबल तरीकों पर जोर
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार पर जोर ■

विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी अनुसंधान को प्रोत्साहन

डिजिटल इंडिया से बदल रहा है भारत का स्वरुप, घर-घर में हो रहा इंटरनेट से शिक्षा और रोजगार का सृजन, भारत में हो रहा है सेमीकंडक्टर और एआई का उदय। मोदी सरकार ने ठाना है, भारत को विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ बनाना है

आधुनिक विज्ञान की तरफ पहल

- सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट
- इंडियन एआई मिशन के अंतर्गत 10,372 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन
- बहुत ही कम समय में 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का निर्माण

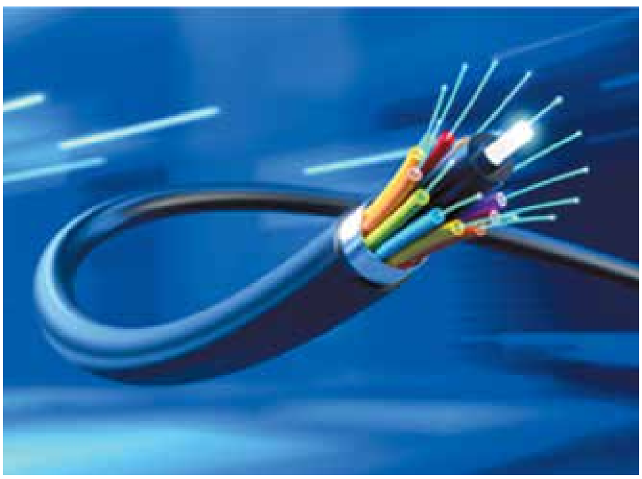

डिजिटल इंडिया से कायाकल्प

- स्वदेशी यूपीआई से पूरे विश्व में लायी रियल टाइम पेमेंट में क्रांति, पूरे विश्व के 46% रियल टाइम पेमेंट्स भारत से उत्पन्न
- डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर से 34 लाख करोड़ रुपये ट्रान्सफर कर बिचौलियों का भ्रष्टाचार समाप्त किया
- फर्जी नामों को चिन्हित कर 2.73 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत
- प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभार्थियों को प्रशिक्षण
- इंटरनेट कनेक्शन में 231% (83.4 करोड़) की वृद्धि के साथ पिछले 10 वर्षों में इंटरनेट की कीमत 97% कम हुई
- भारतनेट के तहत 1.8 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया

- ग्रामीण भारत में टेलीफोन कनेक्शन 2014 में 37.7 करोड़ से बढ़कर जनवरी, 2023 में 51.78 करोड़ हुए
- CoWIN प्लेटफॉर्म के माध्यम वैक्सीन वितरण में समानता और पहुंच सुनिश्चित हुई
- डिजिटल इंडिया के तहत 5.47 लाख परिचालित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)
- प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर, 2022 को 5G सेवाओं की शुरुआत की ■

पूर्वोत्तर

भारत का विकास इंजन

पूर्वोत्तर, भारत की 'अष्टलक्ष्मी' है। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम विकास कार्य को सूरज की पहली किरण की तरह पूर्वोत्तर तक पहुंचाते रहे हैं। भाजपा सरकार में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे इस क्षेत्र का त्वरित विकास संभव हुआ है

शांति के लिए पहल

- AFSPA क्षेत्रों में 75% कमी
- असम-मेघालय सीमा समझौता, 2022
- NSCN(IM) के साथ 2015 में बुनियादी समझौता
- आदिवासी असम शांति समझौते, बोडो, ब्रु-रियांग, त्रिपुरा और कार्बी शांति समझौते किए गए
- 2014 की तुलना में 2022 में उग्रवाद की घटनाओं में 76% की कमी
- 2014 की तुलना में 2022 में नागरिक मौतों में 97% की कमी
- 2014 की तुलना में सुरक्षा बलों की मौतों में 90% की कमी

बुनियादी ढांचे का विकास

- असम में सबसे लंबे रेल-रोड पुल बोगीबील ब्रिज का निर्माण
- सभी राज्यों की राजधानियों को ब्रॉड-गेज रेलवे ट्रैक से जोड़ा जा रहा है
- उत्तर पूर्व में रो-रो सेवा शुरू कर यात्रा को सुगम बनाया गया
- 2022 में पहली मालगाड़ी मणिपुर के तमेंगलोंग स्थित रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पहुंची
- मेघालय को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली
- अखौरा-अगरतला नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन
- तवांग को हर मौसम में संपर्कता प्रदान करने के लिए सेला सुरंग का निर्माण किया गया
- पिछले 10 वर्षों में 7 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं
- डोनर (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 5जी एप्लिकेशन की शुरुआत की
- पूर्वोत्तर में 855.85 करोड़ रुपए की नौ परियोजनाएं स्वीकृत की गईं ■

विश्वमित्र बन उभरा भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने जी-20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज दुनिया भारत को एक जिम्मेदार देश के रूप में देखती है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के तहत हमारा योगदान और मानवीय सहायता के प्रावधान, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, वैश्विक शांति, सुरक्षा और एकजुटता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है

- वंदे भारत मिशन के माध्यम से 2.97 करोड़ भारतीयों का सुरक्षित प्रत्यावर्तन (कोरोना के दौरान) और सूडान, यूक्रेन, लीबिया और यमन से लगभग 30,000 से अधिक भारतीयों का सुरक्षित बचाव
- वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 से अधिक देशों में 30 करोड़ से अधिक COVID-19 वैक्सीन पहुंचाई
- **ऑपरेशन दोस्त :** भूकंप प्रभावित सीरिया और तुर्की में 5,945 टन राहत सामग्री भेजी
- संकट काल में श्रीलंका को आर्थिक सहायता व अन्य पड़ोसी देशों में राहत कार्य

- भारत में जी-20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन
- 2014 के बाद से पाकिस्तानी जेलों से 2,700 से अधिक भारतीय कैदियों की रिहाई

- प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में 2015 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया
- माननीय प्रधानमंत्री की पहल से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया व 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया
- अमेरिका व अबू धाबी में भव्य मंदिर का निर्माण
- सात देशों में भुगतान करने के लिए अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) उपलब्ध
- आतंकवाद निरोधक समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत ने इतिहास में पहली बार भारतीय धरती पर UNSC की बैठकें आयोजित की
- संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, बहरीन, मिस्र और फिलिस्तीन सहित कई देशों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया ■

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर

मोदी की गारंटी

- रेल बजट आवंटन में 9 गुना एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग के बजट में 940 प्रतिशत की वृद्धि की
- देश की विद्युत उत्पादन क्षमता 248,554 मेगावाट से 70 प्रतिशत बढ़कर 425,536 मेगावाट हुई
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ घरों का निर्माण किया गया
- राष्ट्रीय राजमार्गें की कुल लंबाई में 60 प्रतिशत एवं फोर-लेन राजमार्गें की लंबाई में 2.5 गुना की बढ़त हुई
- ग्रामीण क्षेत्रों में 3,44,082 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 1.77 लाख करोड़ रुपये की लागत से किया गया
- मजबूत आधारभूत संरचना का विकास
- बोगीबील पुल, अटल सेतु, कोसी रेल पुल, पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और पारादीप रिफाइनरी का कार्य पूर्ण हुआ
- 2018 में एशिया के दूसरे सबसे लंबे बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल का उद्घाटन हुआ जिसके निर्माण से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा का समय चार घंटे कम हुआ
- दुनिया की सबसे लंबी 9.02 कि.मी लम्बी राजमार्ग अटल सुरंग का निर्माण हुआ

- पूर्वोत्तर के राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए दुनिया की सबसे लंबी द्वि-लेन सेला सुरंग का निर्माण किया
- मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (अटल सेतु) का उद्घाटन किया, जो मुंबई-नवी मुंबई की यात्रा के समय को 20 मिनट तक कम करता है
- विश्व में सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल का निर्माण किया
- बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने हेतु पेरीफेरल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को पूरा किया
- वर्ष 2014 में मेट्रो सेवा केवल 5 शहरों में थी, वर्तमान में यह 21 शहरों में संचालित हो रही है
- मोदी सरकार द्वारा कोच्चि जल मेट्रो का उद्घाटन किया गया
- 4,965 करोड़ की लागत से निर्मित कोलकाता अंडरवाटर मेट्रो

लाइन संचालित हुई जो भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो है
- फास्टटैग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में 8 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ फास्टटैग के माध्यम से 1.4 लाख करोड़ से अधिक लेन-देन हो चुके हैं
- रेलवे और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है, जिसमें 149 हवाई अड्डों के साथ 24 राज्यों में 80 से अधिक स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, साथ ही बंदरगाह क्षमता भी दोगुनी हो गई है
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत ईस्टर्न डी.एफ.सी. पूरी हो चुका है और वेस्टर्न डी.एफ.सी. का 78% काम पूरा हो चुका है
- यू.पी.आई. और कोविन प्लेटफॉर्म जैसी पहल से भारत को वैश्विक पहचान मिली, साथ ही 50% भारतीय आबादी अब सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं
- अमृत, पी.एम.ए.वाई.यू. और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं से शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में 12 गुना निवेश बढ़ा है
- भारत ने एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 130% की वृद्धि हासिल की है ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)............................ (2)............................

ईमेल : ....

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.............................. दिनांक :.......................... बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

अगरतला (त्रिपुरा) में 17 अप्रैल, 2024 को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य नेतागण

17 अप्रैल, 2024 को रामलला के सूर्यतिलक का दर्शन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पूर्णिया (बिहार) में 16 अप्रैल, 2024 को एक विशाल रैली को संबोधित करने से पूर्व जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य नेतागण

मैसूर (कर्नाटक) में 14 अप्रैल, 2024 को एक विशाल जनसभा में जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवेगौड़ा एवं एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेतागण

मंगलुरु (कन्नड़) में 14 अप्रैल, 2024 को एक भव्य रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
60 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 27 अप्रैल, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह